



बस्तर में नक्सल ढांचा ढ्हा

अंतिम कमांडर सोड़ी केशा 42 साथियों के साथ हैदराबाद में किया सरेंडर

बस्तर। छत्तीसगढ़ से लगे राज्य तेलंगाना से आई एक बड़ी खबर ने दक्षिण बस्तर में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। नक्सलियों की बटालियन के अंतिम कमांडर सोड़ी केशा ने अपने 42 साथियों के साथ हैदराबाद में पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी सौंपे हैं।

बताया जा रहा है कि सोड़ी केशा लंबे समय से दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों की आखिरी मजबूत कड़ी था, जिसने करंगुट्टा की दुर्गम पहाड़ियों को अपना ठिकाना बना रखा था। हिड्डमा के एनकाउंटर और बारसे देवा के सरेंडर के बाद संगठन की कमान पूरी तरह सोड़ी केशा के हाथों में आ गई थी, लेकिन लगातार दबाव और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के चलते अब उसने भी हथियार डाल दिए। इस बड़े समर्पण के साथ ही दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों की आखिरी



संगठित टुकड़ी भी खत्म मानी जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 42 माओवादियों के सरेंडर के बाद इलाके में नक्सल संगठन अब लगभग पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। लगातार ऑपरेशन, रणनीतिक दबाव और सरेंडर पॉलिसी के असर से अब बस्तर में नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में

शामिल हैं—

एके-47 राइफल- 5

एसएलआर और इंसास राइफल - कई, 303 राइफल, 8द्वद्व और 9द्वद्व पिस्टल, 38 रिवाल्वर, देशी हथियार और शॉटगन, कुल हथियार -36, कुल गोलियां - 1007, ग्रेनेड -2

इसके अलावा नक्सलियों ने करीब 800 ग्राम सोना भी सुरक्षा बलों को सौंपा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर घोषित इनाम की राशि, सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों पर सरकार ने अलग-अलग कैडर के हिसाब से इनाम घोषित कर रखा था।

राज्य समिति सदस्य -20 लाख, डीवीसीएम -8 लाख, एसीएम -5 लाख

क्षेत्रीय समिति सदस्य -4 लाख, पार्टी सदस्य -1 लाख

इन सभी को मिलाकर कुल इनामी राशि करीब ?1 करोड़ 93 लाख थी, जिसे छोड़कर ये सभी मुख्यधारा में लौटे हैं।



राज्यसभा सांसद बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान बिहार एनडीए नेताओं के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज राज्यसभा से अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। आज दोपहर 12:12 बजे उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली।

ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार

लेबनान में सीजफायर लागू होने तक कोई डील नहीं, आज पाकिस्तान में बातचीत होनी है

नई दिल्ली। इजराइली हमलों के बाद अब तक लेबनान में हजारों पर तबाह हो गए हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर डील में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं हो जाता वह बातचीत नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जनरल ने खबर दी थी कि ईरानी डेलीगेशन गुरुवार शाम पाकिस्तान पहुंच गया

है। इसमें संसद अध्यक्ष गालिबाफ और विदेश मंत्री अराघची शामिल हैं। हालांकि फार्स न्यूज ने इसे फेक बताया। इससे पहले 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के लिए सीजफायर पर सहमत हुए थे। यह भी तय हुआ था कि दोनों देश के नेता पाकिस्तान में मीटिंग के लिए मिलेंगे। यह बातचीत कल यानी



शनिवार को इस्लामाबाद में होना है। इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरान पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर बातचीत में

शामिल नहीं होगा। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं हो जाता वह बातचीत नहीं करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमेंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और उसका वहां जाने का कोई प्लान भी नहीं है। एजेंसी ने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें कहा

गया था कि ईरानी टीम बातचीत के लिए पहुंच चुकी है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले खबर दी थी कि बातचीत शुरू करने के लिए ईरानी प्रतिनिधिमेंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि किसी भी शांति वार्ता के लिए जरूरी है कि अमेरिका सभी मोर्चों पर सीजफायर का पालन करे, खासकर लेबनान में। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है।

प्रमुख समाचार

बंगाल भाजपा के विकास एजेंडे का समर्थन कर रहा: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच दावा किया है कि राज्य की जनता भाजपा के विकास एजेंडे के साथ खड़ी है। उन्होंने आसनसोल रैली की झलकियां साझा करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, आसनसोल में रैली के दौरान जनता का उत्साह यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल बलावोल के लिए तैयार है। करीब 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग रैली में मौजूद नजर आए, जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए समर्थन में नारे लगा रहे थे। रैली के दौरान एक खास दृश्य भी सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और पश्चिम बंगाल के नक्शे के साथ एक पोस्टर प्रदर्शित किया। इस पोस्टर में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, घुसपैट, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हुए राज्य को बचाने की अपील की गई थी।

हरिवंश राज्यसभा के मनोनीत सांसद बने

नई दिल्ली। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अब मनोनीत सांसद बन गए हैं। हरिवंश को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था। उनकी पार्टी छठ ने इस बार उनका नाम नहीं दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन किया। रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद उनकी सीट खाली हो गई थी। इसे भरने के लिए के हरिवंश को चुना गया। 69 साल के हरिवंश अब 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत सांसद होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ही तय करते हैं। इन सांसदों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है। इधर, बिहार के छरू नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा सांसद की शपथ ली। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच दूरी नजर आई।

ऐसी अमर भाषा कहाँ से लाते हैं: सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सीजेआई सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता को कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जाति जनगणना रोकने, संसाधनों के पुनर्वितरण को जनसंख्या उत्तरदायित्व से जोड़ने और एक बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीतियां बनाने का निर्देश देने वाली याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा, %%आप इस याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा कहाँ से सीखते हैं? ये बदतमीजी की भाषा कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? आप लोग याचिका कैसे लिखते हैं? अदालत ने जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए याचिकाकर्ता की आलोचना की। सीजेआई सूर्यकांत ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता से कहा, आपने अपनी याचिका में बदतमीजी की भाषा लिखी है।

मतदाता सूची फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को फ्रीज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर नई याचिका के साथ लिखित याचिकाओं पर भी विचार करने पर सहमति जताई। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान वाली विधानसभा सीटों के लिए नौ अप्रैल को मतदाता सूची को अंतिम रूप देते हुए फ्रीज कर दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। मतदाता सूची फ्रीज करने के खिलाफ वकील ने दी क्या दलील? सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष एक वकील ने मतदाता सूची को फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।

अखिलेश के दांव को काउंटर करेंगे योगी-जयंत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान न हुए हो, लेकिन चौधरियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी यूपी सियासी प्रयोगशाला बनता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुर्जर बहुल दादरी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर गुर्जर-मुस्लिम समीकरण बनाया। उसी दिन मेरठ के सकौती गांव में जाट समाज के मसीहा वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण के बाद से पश्चिम यूपी में जाट बनाम ठाकुर का सियासी तापमान गर्म है। योगी सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने नोएडा से मिशन-2027 का आगाज किया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी से चुनाव बिगुल फूंकने उतर रहे हैं।

राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव 2026

प्रथम चरण के मतदान में बदलते राजनीतिक संकेत

विनोद कुमार सिंह

हमारा लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जनचेतना की वह जीवंत धारा है, जो समय-समय पर अपने स्वरूप, अपने तेवर और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करती है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण - असम, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सम्पन्न मतदान - इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रखर और व्यापक प्रतिबिंब बनकर सामने आया है। यह चरण केवल मतपेटियों तक सीमित एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनमत की वह गूंज है जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आहट,

राजनीतिक पुनर्संतुलन की छाया और भविष्य की राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा सुनाई देती है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास रिकॉर्ड मतदान यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक भागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी

आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि वहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का मंच बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत है। यह उत्साह जहां एक ओर



सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती का संकेत देता है, वहाँ दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है, तो उसे पुनः अवसर भी मिल सकता है। केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में बलवान प्रतीत होता है, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहाँ का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का

प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है, जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय के लिए जिम्मेदारी के रूप में देखा है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का उत्साह क्षेत्रफल या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जनभागीदारी की भावना पर आधारित होता है। छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं।

यह मतदान न केवल राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित है। इस प्रथम चरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता संरचना में हो रहा परिवर्तन है। लगभग 5.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र अब केवल संख्याओं का खेल नहीं, वरन विविधता और समावेश का उत्सव बन चुका है। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे सशक्त संकेत है। केरल और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे अधिक

होना केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। महिलाएं अब केवल मतदान करने वाली इकाई नहीं, बल्कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी हैं। उनके मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं - चाहे वह महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा हो या सुरक्षा। राजनीतिक दलों ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी नीतिनैतियों में बदलाव किया है और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं और घोषणाएं प्रस्तुत की हैं। यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में महिला मतदाता भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

डी-मार्ट का अतिक्रमण हटा, होंडा शोरूम की पार्किंग सील

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने बहतराई रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार दोपहर बहतराई रोड से सुरुस कॉलेज रोड तक करीब चार घंटे चले अभियान में डीमार्ट की ओर से सड़क की 15 फुट जमीन पर लगाई गई लोहे की ग्रिल हटाई गई। लक्ष्मी जेनेरिक और रेफ्रिजरेशन के बोर्ड और शेड भी हटाए गए। इस कार्रवाई के दौरान होंडा शोरूम की पार्किंग को भी सील किया गया। सरकंडा में बार-बार जाम लगने की

शिकायतों के बाद हाल ही में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने मौके का निरीक्षण किया था। उनके दौर के बाद ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम हरकत में आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटया जाता है, वहां कुछ समय बाद फिर से कब्जा हो जाता है। निगम अमला दोबारा निगरानी नहीं करता, जिसके कारण यह समस्या बनी रहती है। जिन स्थानों पर कार्रवाई हुई, वे लंबे समय से निगम नियमों का उल्लंघन कर रहे

बिलासपुर कलेक्टर-एसएसपी के निरीक्षण के बाद निगम ने की कार्रवाई



थे। निगम के सब इंजीनियर जुगल सिंह ने बताया कि बहतराई रोड पर डी मार्ट के संचालक ने रोड की जमीन पर कब्जा कर 15 फुट तक ग्रिल लगा कर बाइंड्री बना ली थी,

सर्विस स्टेशन के ऊपर होटल और नीचे सर्विस स्टेशन है। बिल्डिंग में बेसमेंट पार्किंग नक्शे में दर्शाई गई है, लेकिन पार्किंग की जगह सर्विसिंग के लिए आई बाइक और ट्रेनिंग, अन्य कार्यों के लिए कार्यालय का उपयोग किया जा रहा था, जिसे निगम की टीम ने सील कर दिया। इसी प्रकार साईंस कालेज के आगे ब्यूटी पार्लर के नीचे बेसमेंट पार्किंग में ताला लगाकर उसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसे सील कर दिया गया।

सरगुजा में रिटायर्ड टीचर से 10 हजार रिश्व त लेते बाबू को एसीबी ने किया गिरफ्तार

सरगुजा। सरगुजा में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ममता पटेल की अदालत ने 10 हजार रुपये रिश्तत लेते पकड़े गए बाबू को तीन वर्ष की कैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरगुजा के बीईओ कार्यालय के बाबू ने रिटायर्ड टीचर से 10 हजार रुपये की रिश्तत मांगी थी। एसीबी की टीम ने वर्ष 2020 में उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक, बतौली ब्लॉक के मिडिल स्कूल घोघरा में पदस्थ हेडमास्टर बरनावास मिंज 28 फरवरी 2017 को रिटायर हुए थे। उन्हें अवकाश नकदीकरण का छह लाख रुपये तथा सातवें

वेतनमान के एरियर्स का एक लाख कुल सात लाख रुपये मिलना था। बरनावास मिंज ने इसके लिए बीईओ आफिस के बाबू प्रमोद गुप्ता से संपर्क किया। बाबू प्रमोद गुप्ता को रिटायर्ड हेडमास्टर बरनावास मिंज ने बिल देयक तैयार करने के लिए पांच हजार रुपये रिश्तत दी। बाद में बाबू प्रमोद गुप्ता ने बरनावास मिंज को झांसा दिया कि पहले सातवें वेतनमान एरियर्स की राशि प्रदान करने के लिए बरनावास मिंज ने परेशान होकर इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। 30 दिसंबर 2020 को एंटी करप्शन

ब्यूरो की टीम ने बतौली बीईओ कार्यालय में कार्रवाई करते हुए 10 हजार की रिश्तत लेते लिपिक प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार किया था।

मामले में प्रकरण विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ममता पटेल की अदालत में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ममता पटेल की अदालत ने आरोपी लिपिक प्रमोद गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को तीन वर्ष कठोर कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

राज्य के 10 किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीशों की हुई पदस्थापना



बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के 10 किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीशों की पदस्थापना आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक न्यायिक अधिकारी कल्पना भगत को अंबिकापुर, दिव्या गोयल को जशपुर, सविता सिंह ठाकुर को बिलासपुर, सिद्धार्थ आनंद सोनी को जांजगीर, आरती ठाकुर को बेमेतरा, माधुरी मरकाम को राजनांदगांव, अंशुल वर्मा को गरियाबंद, अंकिता तिग्गा को कांकेर, अरूण नोंगे को महासमुंद, विनय कुमार साहू को धमतरी एवं

मीनू नंद को सुकमा किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीश के पद में पदस्थ किया गया है।

हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर खिलेश्वरी सिन्हा को विधि एवं विधार्थी कार्य विभाग रायपुर के अधिसूचना पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित अपराधों को छोड़कर, ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण सीबीआई द्वारा किया गया हो, उसकी जांच एवं विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश के पद में पदस्थ किया गया है। न्यायालय का मुख्यालय रायपुर होगा।

घर से 20 लाख के सोना-चांदी और नगदी चोरी

सक्ती। जिले के बहेराडीह गांव में बीती रात एक बड़ी चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने गजराज सिंह चंद्रा के घर लाखों रुपए के जेवरत और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, चोरों ने घर से करीब 15 तोला सोना, 85 तोला चांदी के जेवरत और लगभग 60 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।सुबह जब परिवार को चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जैजैपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

रायगढ़ में 4 खाद्य संचालकों को नोटिस जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिले में खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग खाद-बीज दुकानों की जांच कर रहा है, ताकि आगे किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें समय पर सामग्री मिल सके। जांच टीम ने पुसौर और रायगढ़ ब्लॉक की दुकानों का निरीक्षण किया। गड़बड़ी मिलने पर 14 टन खाद जन्क की गई, साथ ही 4 संचालकों को नोटिस जारी किया गया।

जानकारी के अनुसार, जिला निगरानी टीम ने पुसौर विकासखंड के उर्वरक विक्रय केंद्रों में छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान प्रभात ट्रेडर्स पुसौर से 5 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट, अग्रवाल खाद भंडार पुसौर से 9.225 टन नीम लेपित सूरिया बिना पीओएस स्टॉक के मिला। कुल 14.225 टन उर्वरक जब्त किया गया। जन्त सामग्री कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

रायगढ़ ब्लॉक के शंकर ट्रेडिंग कंपनी, कोतरा और सेवा



सहकारी समिति बायंग में अभिलेख अपूर्ण मिले, जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। घरघोड़ा क्षेत्र के महामाया जनरल स्टोर और अग्रवाल खाद भंडार में पीओएस और भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया, जिस पर नोटिस दिया गया है।

कृषि विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार और बुधवार को 16 दुकानों की जांच की गई। बुधवार तक 5 दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

निरीक्षण के दौरान कई जगह स्टॉक का संधारण सही तरीके से

बिलासपुर में आज से बिकेंगे अंडे-चिकन

■ **पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां ही बेची जाएंगी, 2 महीने तक बाहर से नहीं ला सकेंगे**

बिलासपुर। बिलासपुर के कोनी स्थित सरकारी कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 25 मार्च से 1 से 10 किमी तक के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर चिकन और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब प्रशासन ने इसमें आंशिक छूट दे दी है। व्यापारी अपनी दुकानें खोलने के साथ ही चिकन और अंडे बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं।

पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक (जैडी) डॉ. एसएस तंवर ने बताया कि जिन पोल्ट्री फार्मों में जितना स्टॉक उपलब्ध है, केवल उसी की बिक्री की अनुमति दी गई है। अगले दो महीनों तक कोई भी व्यापारी बाहर से नया माल लाकर बिक्री नहीं कर सकेगा।

जिला प्रशासन ने इस पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। निरमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि



पशु चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 10 किमी तक के क्षेत्र की लगातार निगरानी की जाएगी। केंद्र और राज्य की टीम ने लगातार तीन दिनों तक संक्रमित और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। करीब 18 दिन बाद व्यापारियों को राहत मिली है, लेकिन यह सीमित है। एक व्यापारी के अनुसार मौजूदा स्टॉक 8 से 10 दिनों में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद कारोबार ठप होने की स्थिति बन सकती है। संक्रमित क्षेत्र से बाहर 1 से 10 किमी के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। यहां भारत सरकार के पोस्ट

ऑपरेशन सर्विलांस प्लान के तहत हर 15 दिन में नमूने लिए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 25व क्षेत्र से सैंपल कलेक्शन होगा, जिससे तीन माह तक चार चरणों में पूरे क्षेत्र की जांच पूरी की जाएगी। सभी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही क्षेत्र को रोगमुक्त घोषित किया जाएगा।

एपिसेंटर यानी 0-1 किमी क्षेत्र में कम से कम 3 महीने तक पक्षियों के पालन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और क्षेत्र को रोगमुक्त घोषित किए जाने के बाद ही गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी।

12 फीट ऊपर से गिरा स्टील प्लांट का कर्मचारी

■ **रायगढ़ में बायरल फायर मैन गंभीर रूप से घायल, आईसीयू में भर्ती**

रायगढ़। रायगढ़ जिले में स्थित रूपाणाधाम स्टील प्लांट में काम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 10-12 फीट की ऊंचाई से गिरने पर बायरल फायर मैन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना पूंजीपथरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार गेवानी स्थित रूपाणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड में रोज की तरह काम चल रहा था। बुधवार रात प्लांट के बायरल क्षेत्र में बायरल फायर मैन के पद पर कार्यरत दीपक चौहान (22) निवासी राबो, ड्यूटी पर था। इसी दौरान वह

अचानक लगभग 12 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हादसा देख अन्य श्रमिकों ने तुरंत कंपनी प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद घायल दीपक को गंभीर हालत में फोर्टिस जिंदल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि घटना की घटना के बाद टीम प्लांट पहुंची थी।

बयान लेकर जांच की गई, लेकिन यह उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में होश आने पर जांच का बयान लिया जाएगा। बाँडी में चोट का निशान नहीं है। अभी आईसीयू में भर्ती है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

अखिल भारतीय रेल क्रिकेट प्रतियोगिता में दप्पूमेरे टीम उपविजेता

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की क्रिकेट टीम ने अखिल भारतीय रेल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का गौरव प्राप्त किया। फाइनल मुकाबले में टीम ने मेट्रो रेलवे के विरुद्ध शानदार संघर्ष का परिचय दिया और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रसिद्धि प्रतियोगिता का लीग चरण चेन्नई में तथा नॉकआउट चरण मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर की विभिन्न रेलवे टीमों ने भाग लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का प्रभावशाली सफर तय किया। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की क्रिकेट टीम ने पिछले चार वर्षों में तीन बार फाइनल में स्थान बनाकर पदक सुनिश्चित किया है, जिसमें एक स्वर्ण पदक एवं दो रजत पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं उत्कृष्ट खेल भावना की दशाती है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपरांत आज टीम के खिलाड़ियों ने महाप्रबंधक तरुण प्रकाश से शिष्टाचार भेंट की।

न्यायिक मजिस्ट्रेट को खुद को नक्सली बताकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से न्यायपालिका को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गुंडरदेही में पदस्थ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन को एक गुमनाम पत्र के जरिए उनके और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन को एक बंद लिफाफा मिला। जब पत्र खोला

गया, तो उसमें मजिस्ट्रेट और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने की बात लिखी थी। धमकी देने वाले ने जान बख्शने के बदले 3 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है।

हर्रान करने वाली बात यह है कि पत्र लिखने वाले ने खुद को नक्सली संगठन से जुड़ा बताया है। हालांकि, पुलिस इस दावे को लेकर बेहद सतर्क है। बालोद पुलिस पता कर रही है कि यह वाकई नक्सलियों की कोई साजिश है या फिर किसी शरारती तत्व ने पुलिस को गुमराह करने और दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों के नाम का सहारा लिया है।

बालोद में दूध गंगा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सील

■ **कलेक्टर समेत प्रशासनिक टीम ने जायजा लिया जहां खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन साफ दिखा. दूध-गंगा यूनिट प्रशासन का एक उपक्रम है.**

बालोद। प्रशासन का उपक्रम और बालोद जिले का प्रतिष्ठित दूध गंगा पर कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में लापरवाही और गंदगी का अंवार मिला। इसके बाद से कलेक्टर ने उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक टीम शुक्रवार को बालोद शहर का जायजा लेने पहुंची थी। जहां दूध गंगा में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गंदगी या देखी इसके बाद यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चीजें अस्त व्यस्त थी, मॉक्खियां भी घूम रही थी इसके लिए जुर्माने



के साथ जांच के निर्देश दिए हैं। तब तक के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को बंद करने निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूध के सैंपल लेकर लैब टेस्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें यह यूनिट प्रशासन का एक उपक्रम है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों में कमियां पाई गईं। मिठाई निर्माण इकाई और तैयार सामग्रियों में शुद्धता और साफ-सफाई की कमी मिली। फ्लोर बेस के गड्ढों में जमे पानी

से दुर्गंध आ रही थी। वहीं निर्माण कार्य में लगे हलवाईयों द्वारा कैप (टोपी) और ग्लव्स जैसे आवश्यक सुरक्षा संसाधनों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था। दूध गंगा फैक्ट्री की बदहाल स्थिति देखकर कलेक्टर नाराज हो गईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नाली का गंदा पानी सीधे परिसर में फैल रहा था। जहां मिठाइयां तैयार कर रखी गई थीं, वहां भी साफ-सफाई का अभाव था। दुकान के सामने नालियों में कीड़े बजबजाते नजर आए, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने तत्काल फैक्ट्री सील करने के निर्देश दिए। हालांकि किसानों से दूध का क्रय एवं विक्रय निरंतर जारी रहेगा ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। चिर्लिंग और स्टोरेज यूनिट को खुला रखा गया है ताकि आम उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति में कोई असुविधा न हो। संस्था को उपरोक्त कमियों को सुधारने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

तेज धूप में डटे ट्रैफिक जवानों को एसएसपी ने बढ़ाया हौसला

दुर्ग। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। सेक्टर-6 स्थित ग्लोब चौक के पास एसएसपी विजय अग्रवाल ने यातायात पुलिस के जवानों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें धूप से बचाव के लिए गमछा और वॉटर बॉटल वितरित किया। इस मौके पर ट्रैफिक एसएसपी त्रन्ना मिश्रा भी मौजूद रहीं। जवानों से बता दें कि इन दिनों दुर्ग जिले में तापमान 37एण्ट से 39एण्ट के बीच बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय तेज गर्मी और लू जैसे हालात महसूस हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर लगातार अपनी

जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तेज धूप में घंटों खड़े रहकर यातायात व्यवस्था संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए रस्कन ने खुद मौके पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें जरूरी सामग्री प्रदान की। एसएसपी ने बताया कि आगे चलकर जवानों को टोपी भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे धूप से और बेहतर तरीके से बच सकें। इसके साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं में मौत का खतरा काफी कम हो जाता है।

कोटपा अधिनियम के तहत बीरगांव निगम ने 13 दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर की टी.एल. बैठक एवं एन-कार्ड बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा निगम आयुक्त युगल किशोर उर्वशा के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न वाडों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 39, 37, 31, 21, 32 एवं 25 में जांच की गई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 13 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही, स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों को तत्काल हटाने की सख्त चेतावनी दी गई। जांच अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कराना, निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र का निर्माण नहीं करना, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना तथा अनिवार्य चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना जैसे उल्लंघनों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। इन प्रकरणों में संबंधित दुकानदारों पर प्रति प्रकरण 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

छत्तीसगढ़ जसम का पहला राज्य

सम्मेलन 12 अप्रैल को

रायपुर। फासीवाद के खिलाफ सृजन और प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित जन संस्कृति मंच (जसम) का पहला राज्य सम्मेलन सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा. इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के तौर पर देश के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक रामजी राय, आलोचक सियाराम शर्मा, जन संस्कृति मंच के महासचिव और पत्रकार मनोज सिंह,आलोचक प्रेम शंकर शामिल होंगे। सम्मेलन में दोस्ताना संगठनों की तरफ से प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर के अध्यक्ष अरुणकान्त शुक्ला, जनवादी लेखक संघ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष डॉ. सुखनंदन सिंह ध्रुव, भारतीय जन नाट्य संघ (इट्पा) के रंगकर्मी साथी शेखर नाग का भी वक्तव्य होगा। उदघाटन सत्र का संचालन दीपक सिंह द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी. इस सत्र में वर्षा बोपचे, सुनीता शुक्ला और समीक्षा नायर के अलावा अशोक मध्प्रदेश के लेखक और संस्कृतिकर्मी हरगोविंद पुरी, भानु प्रकाश रघुवंशी, जसपाल बांगा, महेश कुशवाहा, रयाम सुंदर मुदगल और नीलम सिंह यादव द्वारा जनगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी।सत्र में इंडियन रोलर बैंड की संगीतमय प्रस्तुति के अलावा दुर्गा-भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी और अशोक नगर के कवियों के द्वारा कविता पाठ भी किया जाएगा। सत्र में दुर्ग-भिलाई जसम की ओर से नाटक आओ अब लौट चलें का मंचन भी होगा. मुख्य रूप से यह नाटक हावर्ड जिन लिखित सोहो में मार्क्स का भारतीय संदर्भ में रूपांतरण जयप्रकाश नायर ने किया है जबकि संगीत व निर्देशन सुलेमान खान का है। सांस्कृतिक सत्र का संचालन रूपेंद्र तिवारी और कामिनी त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा।

दो सिंचाई योजना के लिए 6.12

करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बालोद जिले की दो सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 6 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत योजनाओं में विकासखण्ड-डोण्डोलोहारा की भंवरमरा जलाशय के शीर्ष कार्य नहर रिमाडिलिंग, लाईनिंग एवं अन्य 05 पक्के कार्यों को कराने के लिए 2 करोड़ 51 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत, सिंचाई क्षमता 120 हेक्टेयर के विरुद्ध 84.40 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 10.51 हेक्टेयर अतिरिक्त सहित कुल 130.51 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी तरह से विकासखण्ड-गुण्डरहेही की भन्डेपाला पर एनीकट का निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 61 लाख 34 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के निर्माण से निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने



रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल की चाची स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री रामजी वाटिका में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत श्रीमती अग्रवाल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जनरेशन कंपनी के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान

91 प्रतिशत पीएलएफ के साथ डीएसपीएम संयंत्र ने रचा कीर्तिमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह (डीएसपीएम) कोरबा पूर्व ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव एवं पॉवर जनरेशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने जनरेशन कंपनी के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी रिपोर्ट में हमारे संयंत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जिसमें डीएसपीएम कोरबा पूर्व ने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह हमारे कुशल प्रबंधन एवं संयंत्रों के नियमित रख-रखाव का परिणाम है कि निर्धारित मापदण्डों से कई ज्यादा हमारे



संयंत्र ने परफॉर्म कर राष्ट्रीय स्तर पर यह कीर्तिमान हासिल किया है।

डीएसपीएम के दोनों (2×250 मेगावॉट) क्षमता के विद्युत इकाईयों ने 2025-26 में 91 प्रतिशत पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) अर्जित किया है। डीएसपीएम ने सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) एवं सीएसईआरसी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन) के निर्धारित लक्ष्य 85 प्रतिशत से भी अधिक 91 प्रतिशत पीएलएफ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का गौरव बढ़ाया

है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के वार्षिक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन का समग्र प्रदर्शन भी अच्छा रहा है जिसमें 33 संस्थाओं में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी तीसरा स्थान हासिल कर टॉप तीन की श्रेणी में शुमार है। श्री एसके कटियार ने पॉवर जनरेशन कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी को देश के ऊर्जा उत्पादन पटल पर और अधिक सशक्त पहचान मिली है। हम आगे भी अपना सर्वोत्तम प्रस्तुति देते रहेंगे और कंपनी के प्रगति में नित प्रयासरत रहेंगे।

हिन्दी पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत

कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं की संलिप्तता का लगाया आरोप

रायपुर। 12वीं हिंदी पर्चा लीक मामले में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं पर पर्चा लीक का आरोप लगाते है। उन्होंने कहा कि यूपी, मध्प्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक पर भाजपा नेताओं की सांठ-गांठ है।

विकास उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 12वीं बोर्ड हिंदी पर्चा लीक हुए एक माह हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एफआईआर करवाई है। कमिश्नरेंट लागू है, इसके बावजूद एक भी आरोपी नही पकड़ा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर लीक में भाजपा के नेताओं का हाथ है।

वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल की फीस बढ़ाने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय



स्कूलों में ड्रेस समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती थीं, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद न शिक्षकों को भुगतान हो रहा है, न ही पर्याप्त बजट दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब नर्सरी और पीपी वन कक्षाएं भी बंद की जा रही हैं, और फ्री एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, सरकार 150 विवेकानंद स्कूल खोलने की बात कर रही है, जबकि आत्मानंद स्कूल ही ठीक से संचालित नहीं

हो पा रहे हैं। नई योजनाओं के जरिए केवल वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है।

प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना से इलाज नहीं किए जाने पर विकास उपाध्याय ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल इसे व्यवसाय बना रहे हैं, यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो अस्पताल कर्ज लेकर नहीं चल पाएंगे और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।

वहीं सांसद संतोष पाण्डेय ने भगवान राम से पीएम गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि यदि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो जनप्रतिनिधियों को ी सुरक्षा क्यों दी जा रही है। भाजपा नेता केवल प्रधानमंत्री की चादुकारिता कर रहे हैं, और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं।

चुनाव में गाड़ी लगाने वाले मालिकों को मिलेगा किराया

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रायपुर द्वारा चुनाव में जिन वाहन मालिकों की गाड़ी ली थी उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 एवं विधानसभा उपचुनाव 2024

के दौरान अधिग्रहित किए गए वाहनों के किराया भुगतान को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। जिन वाहन मालिकों को वाहनों का किराया नहीं मिला है वे 16 अप्रैल तक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, चुनाव कार्यों के लिए उपयोग में लाई गई स्कूल बसें, यूनिवर्सिटी बसें तथा अन्य छोटे वाहन (जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा आदि) के मालिकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए



पहले भी दो बार अवसर दिया जा चुका है। पहले 30 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वहीं, दूसरी बार 8 अप्रैल 2026 तक आवेदन मांगे गए थे। अब भी जिन वाहन मालिकों को किराया राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 16 अप्रैल तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक-9 में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर में ट्रैफिक जाम से निपटने का नया सिस्टम

अब एक कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिल सकेगी। अब किसी भी सड़क पर जाम लगने की स्थिति में लोग सीधे पुलिस से संपर्क कर तुरंत मदद प्राप्त कर सकेंगे।

इस पहल के तहत एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल या मैसेज के जरिए ट्रैफिक जाम की जानकारी दी जा सकती है। सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस टीम को मौके पर भेजा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य किया जा सके।

पुलिस प्रशासन ने शहर के ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के



लिए तकनीक का सहारा भी लिया है। कंट्रोल रूम से पूरे शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जहां आईटीएमएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। इससे जाम की स्थिति बनते ही तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।

इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी बढ़ाया गया है। अब

स्थिति देखकर पहले से ही वैकल्पिक रास्तों का चयन कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा।

प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल जाम की समस्या को कम किया जा सकेगा, बल्कि शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अधिक प्रभावी और स्मार्ट बनेगा।

महिलाओं में शक्ति संचार का माध्यम बनेगा महिला आरक्षण विधेयक : लता उसेण्डी

महिला आरक्षण बिल राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक सुश्री लता उसेण्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को लोकसभा के पटल में महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम है और इससे महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सुश्री उसेण्डी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है।

सुश्री उसेण्डी ने कहा कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वन्दन अधिनियम पारित किया गया। 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाने की योजना इस बिल के माध्यम से लागू की जाएगी। इस बिल के पारित होते ही महिलाओं को जनप्रतिनिधि के तौर पर 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

सुश्री उसेण्डी ने कहा कि प्रदेश में 2003 में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी और तब से लेकर आज तक प्रदेश में भाजपा सरकार ने महिला सशक्तीकरण की मिसाल प्रस्तुत की है।



भाजपा की सरकार ने सर्वप्रथम महिलाओं को राशन कार्ड के माध्यम से घर की मुखिया के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार महतारी वन्दन योजना के जरिए मोदी की गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए देकर उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही है। प्रदेश में महतारी सदन क निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। सुश्री उसेण्डी ने कहा कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना अहम कदम है। आने वाला समय देश की मातृशक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा।

बिजली जीवन का अहम अंग, इसकी साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना आवश्यक : एमडी शुक्ला

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज मुख्यालय, डंगनिया स्थित राज्य भार प्रेषण केंद्र में राष्ट्रीय स्तर की 7वीं वेस्टर्न रोजन साइबर सिक्योरिटी को-ऑर्डिनेशन फोरम की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में पहले पंचतत्व—भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर—को महत्वपूर्ण माना जाता था, किंतु वर्तमान समय में बिजली को छठवां तत्व माना जा सकता है, क्योंकि इसके बिना विकास और सुख-सुविधाओं की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली के उत्पादन से लेकर परीक्षण एवं वितरण तक पूरा तंत्र कंप्यूटरीकृत प्रणाली पर ऑपरेट होता है, ऐसे में साइबर हमलों के प्रति सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य अभियंता (लोड डिस्पैच) श्रीमती गाइडलाइन ने स्वागत भाषण दिया। प्रथम दिवस में विभिन्न प्रस्तावों



पर चर्चा करते हुए साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुपालन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में ग्रीड इंडिया के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी टी. श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली पर संचालित हो रही है, ऐसे में पूरे तंत्र की साइबर सुरक्षा, उसकी मॉनिटरिंग एवं फॉलो-अप अत्यंत आवश्यक है। वहीं, डब्ल्यूआरएलडीसी के सिसो श्री सत्येंद्र रघुवंशी ने कहा कि साइबर स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके लिए सभी राज्यों को अपने डेटा को सुरक्षित रखते हुए निर्धारित मानकों एवं कार्यपालन अभियंता श्री मनोज आटवे चाहिए। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव के राज्य भार प्रेषण केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी आनलाइन व प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। दूसरे सत्र में छत्तीसगढ़ की जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कर्पनियों के अधिकारी साइबर सुरक्षा सत्रों में अपनी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा किया। साथ ही ग्रीड इंडिया एवं एनटीपीसी के विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा की चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विस्तृत जानकारी दी। एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. सुभोजीत घोष द्वारा पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर विशेष व्याख्यान दिया। इस अवसर पर श्री शेखर गुप्ता, श्री संजय चौधरी, कार्यपालन अभियंता श्री मनोज आटवे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा : दीपक बैज

क्या सरकार साड़ी खरीदी की कसाएणी जांच

जगदलपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर साड़ी खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। श्रुक्वार को जगदलपुर राजीव भवन में पत्रवातां को संबोधित करते हुए बैज ने कहा कि सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है।

दीपक बैज ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए 1



लाख 94 हजार 5 सौ 90 ना घंटिया क्वालिटी की साड़ी की खरीदी की है। साड़ी उपयोग के लायक नहीं है।

विभाग के द्वारा सेनेटरी

पैड, ग्रीन बोर्ड एवं आरओ खरीदी में भी भ्रष्टाचार किया गया है। बैज ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या सरकार कूठित भ्रष्टाचार की जांच कराएगी।

पक्का घर बना तो बरसात की चिंता से मुक्त हुआ जीवन

रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल लोगों को सुरक्षित आवास मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और सम्मान भी बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन की एक मिसाल है ग्राम पंचायत गिरारी के निवासी श्री मदन।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गिरारी गांव में रहने वाले मदन पूर्व में अपने परिवार सहित कच्चे मकान में निवास करते थे। बरसात के मौसम में उनके घर की छत से पानी टपकता था, जिससे परिवार को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। हर वर्ष वर्षा ऋतु उनके लिए चिंता और असुविधा का कारण बन जाती



थी। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मदन को पक्का आवास स्वीकृत हुआ। शासन से प्राप्त आर्थिक सहायता तथा स्वयं के श्रम के समन्वय से उन्होंने अपने सपनों के घर का निर्माण पूर्ण किया। आज उनका परिवार एक

मजबूत, सुरक्षित और व्यवस्थित पक्के घर में निवास कर रहा है। मदन बताते हैं कि पहले बरसात के समय घर में पानी भर जाता था और परिवार को भय बना रहता था, लेकिन अब इस समस्या से पूरी तरह राहत मिल गई है। उनका कहना है कि इस योजना ने उनके जीवन में नया आत्मविश्वास और सुख-शांति का संचार किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इस प्रकार ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आरएसएस-भाजपा: लगातार बढ़ते पेड़ पर अनगिनत फल

अभिलाष खांडेकर

एक पूर्व नामचीन नौकरशाह ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के बारे में लिखा था कि इसमें विचार और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं है। हिंदी में भाजपा का एक नारा खूब लोकप्रिय हुआ... ‘मोदी है तो मुमकिन है’ यानी उनके नेतृत्व में सब कुछ संभव है। मोदी लंबे समय से देश में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन चुके हैं और अब उस दल से कहीं ऊपर उठ चुके हैं जिसने उन्हें 1987 में गुजरात इकाई का महज महासचिव बनाया था। वास्तव में, मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि बनी थी; उनके नेतृत्व में पार्टी इतना फली-फूली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमित शाह के शब्दों में : पिछले कई वर्षों में भाजपा की अखिल भारतीय स्तर पर हुई वृद्धि देश के स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में किसी भी पार्टी द्वारा की गई प्रगति से बेजोड़ है और नरेंद्र भाई की लोकप्रियता ने पार्टी के लिए सतत वृद्धि और दीर्घकालिक संगठनात्मक लाभ सुनिश्चित किया है। मोदी ने अपने भाषण कौशल, संघटनात्मक क्षमता और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए साल-दर-साल नए मतदाताओं और समर्थकों को बड़ी संख्या में जोड़ा है, जिससे भाजपा कहीं अधिक शक्तिशाली बन गई है। वास्तव में, 2014 से पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और अपनी सदस्यता और लगातार जीत के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। पर क्या यही सब काफी है? बदलते समय के साथ-साथ राजनीतिक दलों में भी बदलाव आता है, क्योंकि यही राजनीतिक प्रक्रिया का एकमात्र स्थिर पहलू है। भाजपा भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गई है। वास्तव में, यह पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी है और इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा ‘सेवा’ में विश्वास रखती थी, अब बात कुछ और है। मुझे लता मंगेशकर का यह कथन याद है, ‘नरेंद्र भाई को सत्ता से कोई लगाव नहीं है।’ यह सच हो सकता है लेकिन मोदी के सत्ता से अनासक्ति के मंत्र में इसके कई नेता विश्वास नहीं करते। दूसरे शब्दों में, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए जनसेवा करना। भाजपा कार्यकर्ता अपने सेवाभावी नहीं हैं जितने मोदी हैं या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे इसके कुछ चुने हुए नेता थे। यदि पार्टी इस स्तर तक संख्याबल में बढ़ गई है तो इसका मुख्य कारण स्वार्थी लोगों का बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल होना है, जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में हिस्सा बंटाना है। फिर भी, कई मायों में भाजपा संगठन, जो आगे दो-तीन वर्षों में अपना अर्धशतक पूरा करने जा रहा है, अपने विरोधियों से अतुलनीय है। इसमें अनुशासन की झलक दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है। यह अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें व्यस्त रखने और उन पर कड़ा नियंत्रण रखने में माहिर है। निस्संदेह, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में वामपंथी दलों, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से कहीं अधिक निवेश करती है। वास्तव में, यह एक चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाली पेशेवर पार्टी है। मैं जनसंघ के दिनों से ही भाजपा पर गहरी नजर रखता आया हूं, उसके पूर्ववर्ती स्वरूप से। जनसंघ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्पष्ट छाप थी; जो भाजपा पर अब धुंधली पड़ गई है। क्या जनसंघ भाजपा से बेहतर था? एक तरह से हां, क्योंकि उसने सत्ता का स्वाद नहीं चखा था और भाजपा की तरह सारी बुराइयां नहीं समेटी थीं। जनसंघी सादागीपूर्ण जीवन जीते थे और खाली जेब सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। अब भाजपा के लगातार बढ़ते पेड़ पर, जो अनगिनत फलों से लदा है, लाखों कार्यकर्ता उन फलों को खाने के लिए लालायित दिखते हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस से खुद की अलग पहचान बनाए रखी है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिञ्जलः ।

कलविङ्कः सुराप्रीथमन्नादं यत्स तित्तिरिः ॥5 ॥

ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यस्पीश्वरः ।

संवत्सरान्ते तदधं भूतानां स विशुद्धये ॥6 ॥

भूम्यम्बुदरमयोपिन्द्रयश्चरुधां व्यभजद्वरिः ।17 ॥

अर्थात् (क) दैत्यों की बहिन रचना नामक कल्या त्पश्र की स्त्री हुई। उन दोनों से सन्निवेश और विश्वरूप नामक वीर्यवान् पुत्र पैदा हुवे ॥४॥ । यद्यपि विश्वरूप शत्रुभूत असुरों का दौहित्र था तथापि देवताओं ने उसको अपने यज्ञ में आचार्य रूप से वरण किया ॥ 45 ॥

(ख) हे राजन्! उस विश्वरूप के तीन शिर थे, एक सोम पीने वाला, दूसरा सुरा पीने वाला और तीसरा अन्न खाने वाला ऐसा हमने सुना है॥ 1१॥ यज्ञ के समय इस विश्वरूप ने उन बहिपद देवताओं को खूब ऊंचे स्वर से बोलकर प्रत्यक्ष रूप से भाग दिया

जिनके कि आश्रय में पितृदेव रहते हैं॥ 2॥ परन्तु यज्ञ करते समय विश्वरूप छुपकर असुरों को भाग देने लगा क्योंकि माता के स्नेह से अपने मातृकुल का भी इसे पक्ष रहा ॥ 3 ॥

इन्द्र इसकी इस देवघातिनी धर्म्मविरुद्ध चेष्टा को देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और [भावी अनर्थ की संभावना से] भयभीत होकर तत्काल इसके तीनों मस्तक काट डालें ॥ 4 ॥ उसका जो सोम पीने वाला मुख था कपिंजल बना, सुरा पीने वाला व.लविद्ध, और अन्न खाने वाला तित्तिर हुवा। 5 ॥

यद्यपि इन्द्र में ब्रह्महत्या को न मानने का] सामर्थ्य था तथापि उन्होंने अञ्जलि बौध्दकर स्वेच्छा से ब्रह्महत्या की स्वीकार किया। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह पाप भूतशुद्धि के लिये॥ 3॥ पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों में चार विभाग करके बाँट दिया।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

अशांति की आग से कब तक झुलसता रहेगा मणिपुर?

मनोज कुमार अग्रवाल

मणिपुर फिर जल उठा है। मणिपुर एक बार

फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है और यह केवल एक राज्य का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है लोकसभा की पटल से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज जरूर उगा। उनके उस बयान पर उस समय सदन में ज्यादातर सांसदों मेज थपथपा कर अपना समर्थन दिया था। पीएम मोदी की आवाज में भी एक ऐसा विश्वास था कि सभी मान गए थे कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। अब उस बयान को दो साल पूरे होने को हैं और मणिपुर फिर जल रहा है, मणिपुर फिर कर्फ्यू का दंश झेल रहा है, कई जगहों पर इंटरनेट सस्पेंड हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। मोहरांग क्षेत्र में हुए रॉकेट हमले में दो मामूम बच्चों की मौत ने इस संकट को और भयावह बना दिया है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है. ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. वहीं राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं में आंशिक राहत देने का फैसला किया है, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।

मणिपुर में हालिया हिंसा के दौरान सुरक्षा बल की फायरिंग में घायल हुए एक युवक की बुधवार को मौत हो गई. मृतक को पहचान 31 वर्षीय वांगहेंगबम बांबी के रूप में हुई है. वह बिष्णुपुर जिले के कुंबी तेराखोंग माखा लीकाई का रहने वाला था. इस मौत के बाद फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है. इससे पहले मंगलवार को दो लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे.। यह घटना सिर्फ एक अपराधिक वारदात नहीं, बल्कि उस अस्थिर सामाजिक डांचे का प्रतीक है, जो पिछले कई महीनों से भीतर ही भीतर सुलग रहा था। इस दर्दनाक घटना ने न केवल स्थानीय लोगों के मन में भय और आक्रोश पैदा किया है, बल्कि पूरे देश के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मणिपुर में में शांति कब और कैसे लौटेगी। इस प्रदेश में स्थायी शांति का इंतजार काफी लंबा हो रहा जा रहा है। जिस के सत्राटे में एक घर पर रॉकेट हमला होना, रातमें एक पांच महीने की बच्ची और एक पांच साल



के बच्चे की जान चली जाती है, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है। यह आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटती दुनिया की कहानी है, जिनके लिए जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बिष्णुपुर जिले में इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, वह इस बात का संकेत है कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सड़कों पर उत्तरी भौड़, कर्फ्यू का लागू होना, पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं का बंद होना और सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती ये सभी हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया और जवाब में हुई फायरिंग, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, यह बताता है। है कि हालात कितने नाजुक और विस्फोटक हो चुके हैं। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा का यह नया अध्याय है, जिसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच बढ़ती दूरी और अविश्वास ने इस संघर्ष को लगातार हवा दी है। 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने का बंद कही गई थी, स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों को यह डर सताने लगा कि उनके अधिकारों और संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसके बाद 3 मई 2023 को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया और आज तक यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती, कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं का निबंदन, शांति समिति का गठन और राहत शिविरों का संचालन ये सभी प्रयास इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय है। लेकिन इसके बावजूद हिंसा का दौर जारी है। समुदायों के बीच लंबे समय से जारी हिंसा में तीन सौ से

ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 हजार से ज्यादा लोग अब भी विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं। ऐसे में हिंसा रोकने के लिए जो कदम उठा गए हैं, उसको लेकर सवाल न सवाल यह है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं? क्या ये केवल तात्कालिक समाधान हैं या वास्तव में स्थायी शांति की दिशा में

कोई ठोस पहल ? फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार के गठन के बाद यह उम्मीद थीगी थी कि मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। लेकिन हालिया घटनाएं यह दर्शाती हैं कि राजनीतिक बदलाव से ज्यादा जरूरी है सामाजिक विश्वास का पुनर्निर्माण। जब तक विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और विश्वास की प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी, तब तक शांति केवल एक सपना बनी रहेगी। इस संकट ने राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। डबल इंजन सरकार की अवधारणा, जो केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का दावा करती है, इस समय कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उसे न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है, बल्कि सामाजिक संतुलन भी कायम करना है। कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासन की मांग इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। यह मांग सीधे तौर पर राज्य की एकता और अखंडता के सवाल से जुड़ी है। ऐसे में सरकार के लिए संतुलन बनाना बेहद कठिन हो गया है। एक तरफ उसे समुदायों की भावनाओं को समझना है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा भी करनी है। मणिपुर की मौजूदा स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल सुरक्षा बलों के दम पर शांति कायम की जा सकती है? इसका जवाब स्पष्ट है नहीं। शांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और न्याय से स्थापित होती है। सरकार को चाहिए कि वह सभी पक्षों को एक मंच पर लाए, उनकी बात सुने और एक ऐसा समाधान निकाले जो सभी के लिए एकीकार्य हो। इसके साथ ही, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन लोगों ने इस हिंसा में अपने घर, परिवार और आजीविका खो दी है, उनके लिए केवल राहत

शिविर पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें एक सम्मानजनक जीवन वापस दिलाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए ऐसी खबरों और संदेशों को बढ़ावा देना चाहिए, जो शांति और एकता को मजबूत करें। अफवाहों और भड़काऊ सामग्री से बचना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अंततः मणिपुर का यह संकट हमें यह सिखाता है कि विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है। जब तक हम एक-दूसरे के दर्द को समझने और साझा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार हमें झकझोरती रहेंगी। सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। आज मणिपुर में लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। समुदाय अपने-अपने इलाकों में सिमट गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे हजारों विस्थापित लोग अपने घर लौटने से डरते हैं। ऐसे माहौल में केवल पुलिस या सेना के बल पर शांति कायम नहीं की जा सकती। शांति के लिए जरूरी है संवाद सच्चा, ईमानदार और निरंतर संवाद। सरकार को सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनकी चिंताओं को समझना होगा। केवल राजनीतिक समाधान नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय समाधान की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। लूटे गए हथियारों की बरामदगी, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी, और हिंसक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ये कदम जरूरी हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना रहे, ताकि नागरिक समाज को सुरक्षित महसूस करें, न कि भयभीत। मीडिया और नागरिक समाज की भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका है। अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों को रोकना, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और शांति के लिए माहौल बनाना ये सभी जिम्मेदारियां साझा हैं। आज जरूरत है एक व्यापक, संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की। सरकार, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम जनता सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि मणिपुर की शांति केवल वहां के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है।इस अशांति के पीछे छिपे विदेशी ताकतों के दुष्प्रयासो को भी नाकाम करना होगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले

ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे। इसके अलावा वह समाजसेवी, लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इनको महात्मा फूले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुुरीतियों को बंद करने, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया था। फूले समाज की कुप्रथा और अंधश्रद्धा की जाल से समाजो को मुक्त करवाना चाहते थे। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले का परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर रहने लगा था। इस दौरान परिवार के वरण-पौषण के लिए फूलों के गजरे आदि को बनाने का करने लगे थे। माली के काम में लगे होने के कारण इन्हें फूले के नाम से जाना जाने लगा। साल 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में उनके द्वारा खोले गए इस स्कूल में ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षक बनी थीं। उस दौरान समाज के एक हिस्से ने उनका काफी विरोध किया था। जिसके कारण ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद करना पड़ा था। इसके बाद इसी ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जगह मुहैया करवाई थी। दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 24 सितंबर 1873 को समाज परिवर्तन के आंदोलन को

आगे बढ़ाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शूद्रों-अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र

में रोजगार के अवसर दिलाना, और शिक्षा के लिा प्रोत्साहित करना शामिल था। साल 1888 में ज्योतिबा फूले की समाजसेवा से प्रभावित होकर उनको मुंबई की एक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं थीं। जिसमें छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, तृतीय ख, अछूतों की कैफियत शामिल हैं। उनके संघर्षों के कारण सरकार ने एंग्रीकल्चर एक्ट पास किया था।

ब्राह्मण-पुरोहित के बिना ही ज्योतिबा ने विवाह-संस्कार आरम्भ कराया। जिसे मुंबई के उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली थी। वह बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। जब ज्योतिबा फुले को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई योग्य शिक्षिका नहीं मिली। तब इस काम के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को शिक्षित करने का कार्य किया।

उच्च वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा के समाज सेवा के काम में बाधा डालना शुरू किया। इसके बाद भी जब वह आगे बढ़ते चले गए तो उनके पिता ने ज्योतिबा और सावित्री को घर से निकाल दिया था। इससे कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ था। लेकिन बाद में ज्योतिबा ने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोले।

युद्धविराम पर खतरा मंडराने से भरोसा टूटा?

राजेश बादल

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच देर रात हुए दो सप्ताह के युद्ध विराम पर आखिर विश्व विरादरी को क्यों यकीन करना चाहिए था ? यह ऐसा सवाल था, जो जंगबंदी के ऐलान के साथ ही यक्ष प्रश्न की तरह जानकारों के सामने उपस्थित था और जिसका उत्तर खुद जंग में शामिल देश भी नहीं जानते थे, क्योंकि अमेरिका-इजराइल और पाकिस्तान अपनी घोषणाओं से कब पलट जाएं, कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान एक नकली राष्ट्र है। एक नकली देश असली युद्ध विराम कैसे करा सकता था। वह तो अमेरिका की कठपुतली है।

अन्यथा वह बलोच विद्रोहियों से समझौता कर सकता था, अफगानिस्तान से समझौता कर सकता था और ईरान से तो उसके अनेक मसलों पर गंभीर मतभेद हैं। आज तक बातचीत की किसी मेज पर पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि दरअसल पाकिस्तान में ऐसी कोई मेज है ही नहीं। वह तो घबराए ट्रम्प का हुक्म था। पाकिस्तान ने वही किया। यही उसका चरित्र है।

दुनिया के तमाम मुल्कों की तो बात इसलिए अलग है क्योंकि ट्रम्प उनकी सुनते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रम्प चंद रोज पहले जिस अभेद भाषा और अश्लीलता पर उतर आए थे, उस स्तर पर तो किसी भी देश का प्रमुख नहीं जा सकता था। ट्रम्प की पुस्तक ‘द आर्ट ऑफ द डील’ को अमेरिकी लोग अब निश्चित रूप से रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहेंगे।

चार दशक पहले कारोबारी नजरिये से लिखी गई किताब का आज कोई सियासी अर्थ नहीं रहा है, क्योंकि युद्ध का उन्माद ट्रम्प के ऊपर इस कदर हावी था कि वे समूचे विश्व के मान्य सिद्धांत और मार्गदर्शक निर्देशों को भुला बैठे थे। अंतरराष्ट्रीय संधियों पर अमल नहीं करने की तो उन्होंने जैसे शपथ ले रखी है। राष्ट्रपति एक प्राचीन विरासत और सभ्यता वाले देश को पाषाण युग में पहुंचाने की बात करने लगे थे।



वे भूल गए कि सभ्यता कोई दो-चार साल में विकसित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सभ्यताओं का विकास लंबी, जटिल और बारीक रेशे वाली सामाजिक परिवर्तनों की हजारों साल चलने वाली श्रृंखला से होता है। उसे कोई खतरनाक परमाणु बम गिराकर नष्ट नहीं कर सकता। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से वहां की सभ्यता तो नष्ट नहीं हुई। आज का जापान इसका प्रमाण है। दरअसल अमेरिका के अतीत - गर्भ में ही भयावह विनाशकारी बीज आज भी मरे नहीं हैं, जो गाहे-बगाहे अपने होने का सबूत देने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं। तो फिर अब क्या हुआ ? अमेरिका कभी अस्थिर जिद्दी स्वभाव और आक्रामकता को नहीं छोड़ता। बीते तीन दशक इसके गवाह हैं।

लेकिन इस बार ईरान जैसे एक परंपरागत राष्ट्र ने उसे बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर दिया था। ट्रम्प को उसी शैली में उतर देने वाला इसके पहले नहीं मिला था। अभी तक की सारी बंदरबुष्टदिकियों ने ईरान पर कोई असर नहीं किया था। ईरान के शिया मुसलमान आमतौर पर कट्टर और लड़ाकू नहीं हैं। फिर भी अगर वे मरने-मारने पर आ

जाएँ तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है।

यहाँ उनकी अपनी सभ्यता के बीज भी छिपे हुए हैं, जिन्हें ट्रम्प नष्ट करने पर उतारू थे। यह उनकी खौफनाक भूल थी। अस्सी के दशक में ईरान और इराक कई साल तक युद्ध लड़ते रहे। यह युद्ध बीसवीं सदी के सबसे लंबे और विनाशकारी युद्धों में से एक है। इराक ने ईरान पर आक्रमण किया था। यह जंग आठ साल चली।

इसमें भारी विनाश हुआ था और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ था। क्या

ट्रम्प की सेना आज इतनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है ? इस बार तो इराक समेत नाटो के अनेक देशों ने ट्रम्प से किनारा कर लिया। यूरोपीय देशों ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। आज ट्रम्प के पास अंध समर्थक देशों का कौन सा समूह है ?

शायद कोई भी नहीं। खुद अमेरिका के करोड़ों मतदाता ट्रम्प के इस रवैये पर खफा हैं। अमेरिका में हुए अनगिनत प्रदर्शन इसके साक्षी हैं। यह विडंबना है कि अपना कोष हथियारों और गोला बारूद पर खाली करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की आर्थिक बदहाली देखना ही नहीं चाहते। जबकि अमेरिका पर कुल ऋण 3096 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है।

कर्ज राष्ट्र की कुल जीडीपी का 127 फीसदी से भी अधिक है। इस देश को प्रतिदिन दो अरब डॉलर केवल ऋण का ब्याज चुकाने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक पर करीब एक करोड़ रुपए का ऋण है। यह विश्व में सर्वाधिक है। बताने की जरूरत नहीं कि सैनिक साजो-सामान और गोला-बारूद पर अमेरिका का व्यय सर्वाधिक है।

तटस्थ समीक्षा करें तो पाते हैं कि अमेरिका ने खुद को इन युद्ध जैसी परिस्थितियों में उलझाया है। चाहे वह अफगानिस्तान में किया हो, यूक्रेन का साथ देने पर किया गया हो या फिर ईरान के खिलाफ। इन दिनों अमेरिका में बहस का मुद्दा है कि राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त असौमित अधिकार कहां तक जाजब हैं और क्या अब समय आ गया है जब संविधान की समीक्षा की जाए।

विडंबना है कि इजराइल पूरे मामले में ठगा सा महसूस कर रहा है। सूत्रों की मानें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्ध विराम से पहले नेतन्याहू से विचार-विमर्श भी आवश्यक नहीं समझा। पाकिस्तान और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि लेबनान भी युद्ध विराम में शामिल है। इसके उलट इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक अधिकृत बयान में स्पष्ट किया है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है।

इसलिए इधर जंगबंदी की घोषणा हुई और उधर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। अब अमेरिका और पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। ईरान और अमेरिका दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया था। ईरान और पाकिस्तान के बीच बलूचिस्तान के मसले पर लंबे समय से तनाव जारी है।

फिलहाल ईरान ने युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार तो किया है लेकिन इसके पीछे इरादे क्या हैं, कोई नहीं कह सकता। अमेरिका किसी भी कीमत पर जंग से बाहर निकलना चाहता था। पर इजराइल और ईरान अभी खामोश नहीं बैठेंगे। दो सप्ताह का समय ईरान के लिए काफी था। वह अपनी युद्ध की तैयारियों को नया रूप दे सकता है और नए सिरे से अपने नेतृत्व का चुनाव कर सकता है।

भारत ने शायद ठीक ही ईरान से तत्काल भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। बहुत सारी खुफिया सूचनाएं होती हैं, जो साझा नहीं की जाती हैं। आशंका तो है कि प्रेक्ष द्दिन बाद जंग का कोई नया रूप देखने को मिल सकता है, इसलिए भारतीयों का स्वदेश लौटना ही उचित है।

आज का इतिहास

- 1921 अमीर अब्दुल्ला ने हाल ही में ट्रांसजार्डन के ब्रिटिश रक्षक बनाए गए पहले केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की।
- 1924 पहली मेन्स कॉलेज स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई।
- 1930 ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला जनता के लिये खोला गया।
- 1945 द्वितीय विश्व युद्ध-अमेरिकी बलों ने जर्मनी के वीमर के पास बुचेनवाल्ड एकाग्रता शिविर को मुक्त कर दिया।
- 1951 अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस। ट्रुमैन ने अपने आदेशों के तहत सेना के डगलस मैकआर्थर के जनरल को राहत दी, जो कि कोरिया युद्ध के बारे में सार्वजनिक बयान देते हैं, जिसने प्रशासन की नीतियों का खंडन किया।
- 1951 थिएटर और टेलीविजन अदकारा रोहिणी हट्टगंडी का पुणे में जन्म।
- 1970 अमेरिका ने चंद्रमा अभियान के लिए अपोलो 13 कार्यक्रम शुरू किया।
- 1977 साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का निधन।
- 1979 युगांडा-तंजानिया युद्ध-युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी और तंजानियाई सेनाओं ने युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन टोफली को मचबूर करते हुए कंपाला पर कब्जा कर लिया।
- 1996 संयुक्त राज्य अमेरिका में एक हवाई जहाज को पायलट करने के लिए सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में एक रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करते हुए, विमान सात वर्षीय जेसिका डबरोफ द्वारा उड़ाया गया, जो चेयेन, व्योमिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वह और दो अन्य मारे गए।
- 1999 अगिन 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया।
- 2002 गुरीबा आराधनालय बम विस्फोट से अल कायदा द्वारा ट्यूनीशिया में 21 को मर दिया गया।
- 2003 पाकिस्तान ने 12वॉ बार शारजाह कप जीता।
- 2007 अल्जीरियाई राजनीतिज्ञों ने दो बम विस्फोट से 33 लोग मारे गए और 222 लोग घायल हुए।
- 2008 स्वीडन में वैज्ञानिकों ने आठ हज़ार वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की।
- 2010 राष्ट्रपति पोलज़िन्स्की के जुलूस का गवाह बनने के लिए दस हजार डंडे सड़कों पर जाते हैं, जो राष्ट्रपति भवन, वारसॉ, जहां वह राज्य में झूट बोलेंगे।
- 2011 फ्रांस में, बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लागू होता है।
- 2011 टोहोकू भूकंप के एक महीने बाद जापान में 6.6 तीव्रता का आफ्टरशॉक जापान में गिरा, लगभग एक घंटे तक चला।

कहां गए शांति के कपोत उड़ाने वाले ?

अशोक मधुप

आज की दुनिया बारूद से धधक रही है। रूस-यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक, हर तरफ़ मिसाइलों की गूँज है। शांति की बातें अब सुनाई नहीं देतीं। शांति के कपोत उड़ाने वाले दिखाई देने बंद हो गए। युद्ध की विभिषिका के विरोध में प्रदर्शन करने और मोमबत्ती जलाने वाले अब सड़कों से गायब हैं। युद्ध के विरोध के स्वर धीमे ही नहीं हुए, पूरी तरह खामोश हो गए। बुद्ध के संदेश अब किताबों में ही बंद होकर रह गए हैं। युद्धों के विरोध की क्ति से बात नहीं उठ रही। दुनिया में शांति स्थिर करने के लिए बने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुंह पर टेप चिपक गया। वह देख सकता है। न कुछ बोल सकता है। न आदेश कर सकता है।

विडंबना देखिए कि इक्कीसवीं सदी में हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन के चंद टुकड़ों और आपसी वर्चस्व के लिए हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे। युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, या इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव हो। जीत के झंडे चाहे जिस देश के हाथ आएँ, हारती हमेशा मानवता है। इन युद्ध में विजयी कोई भी हो, सदा पराजित तो मानव होती है। मरती बस ईंसानियत है।

इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कई मंचों से उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नहीं किया। सब देश गुंगे बन कर रह गए। आज भी ये ही हाल है। मरता ईरान खाड़ी

के उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन दाग कर तबाही मचा रहा है, जिनमे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अपनी बरबादी होते देख ये देश ईरान पर अमेरिकी हमलों का उस तरह विरोध नहीं कर रहे, जिस तरह कि करना चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध के समय जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को जन्म दिया तो मध्य पूर्व (इज़राइल-हमास-ईरान) के संघर्ष ने दुनिया को धार्मिक और कूटनीतिक ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इन लड़ाइयों में टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच जो आवाज़ दब जाती है, वह है—एक मामूस्म बच्चे की चीख और एक बेबस माँ की कराह। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिनका राजनीति या सत्ता की लालसा से कोई लेना-देना नहीं होता। यूक्रेन के कीव से लेकर गाज़ा की गलियों और ईरान के गांव तक तक, हज़ारों औरतें और बच्चे मौत की नौद सो चुके हैं। जो उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उस उम्र में बच्चे बमों के धमाकों को पहचानना शुरू रहे हैं। हज़ारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों का भविष्य मलबे के नीचे दब गया है। युद्ध के दौरान महिलाओं को न केवल विस्थापन का दर्श झेलना पड़ता है, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक हिंसा का सबसे आसान लक्ष्य बनती हैं।

युद्ध केवल ईसान को नहीं मारता, वह सदियों से बनी-बनाई सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर गिरते बम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। जब एक अस्पताल पर मिसाइल गिरती है, तो वह केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं ढहती, बल्कि ईंसानियत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इन लड़ाइयों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक



सीमित नहीं है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया। इससे गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया। ईंधन की बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों की कमी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो खरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में खर्च होने चाहिए थे, वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलों बनाने में झोंके जा रहे हैं।

युद्ध का एक और खामोश शिकार हमारा पर्यावरण है। हज़ारों टन गोला-बारूद का इस्तेमाल वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। जंगलों की आग, समुद्री प्रदूषण और ज़मीन में धंसे बारूदी सुरंग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। हम जिस धरती को बचाने की कसमें खाते हैं, उसी को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं। जब हम टीवी पर बमबारी के दृश्य देखते हैं और उन्हें केवल एक न्यूज़ अपडेट की तरह छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर की ईंसानियत मर चुकी है। युद्ध हमें रूबरू बना देता है। हम मौतों को केवल %आंकड़ों% में गिनने लगते हैं। घृणा का यह बीज जो आज बोया जा रहा है, वह भविष्य में और अधिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को जन्म देगा।

अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया है। उसने इराक पर यह कह

कर हमला किया था कि उसके पास कैमिकल और अन्य घातक शस्त्र है। इराक हार गया। सद्दाम हुसैन पकड़े ही नहीं गए, उन्हें फांसी हो गई, किंतु अमेरिका इराक से कुछ भी बरामद नहीं कर पाया। उसका सब झूठा प्रचार रहा। अब ईरान पर यह कह कर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया कि वह परमाणु बम बनाने के नजदीक है। उसकी इस शक्ति को खत्म करना है। हमले जारी है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए अपने मन की बात कह दी कि उसे ईरान के तेल पर कब्जा करना है। तीन जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वेनेजुयला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया प्लोरेस को उनके देश (कराकस) से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद की गई। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। बहाना मादक पदार्थों की तस्करी रोकना था किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुयला का तेल वे बेचेंगे। उनकी मर्जी से बिकेगा। इस सब का मतलब साफ है कि दुनिया के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। वह किसी ने किसी बहाने उन पर कब्जा करना चाहता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है।

फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण दुनिया भर में

तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी देखी जा रहीयह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हाल के दिनों में हमलों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इन्कार करने वाले ब्रिटेन जैसे वह देश होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की वजह से जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं। उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सुझाव है- पहला- अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत है। दूसरा- हिम्मत जुटाओ, जलडमरूमध्य पर जाओ और उसे अपने कब्जे में ले लो।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के बाद खाड़ी देशों से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की है। पूर्व आईईएई प्रमुख ने विनाशकारी सैन्य टकराव की संभावना का जिक्र किया। बारदेई ने एक्स पर एक पोस्ट में पड़ोसी खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए कहा, कृपया, एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि यह पाल शख्स इलाके को आग का गोला बना दे। मोहम्मद अल बारदेई ने अपनी गुहार को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हुए युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस-चीन-फ्रांस को संबोधित एक अलग पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है? युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं

है। इतिहास ने बार-बार सिखाया है कि युद्ध के मैदान में कभी कोई नहीं जीतता, बस जो कम हारता है वह खुद को विजिता घोषित कर देता है। रूस, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान या अमेरिका—शक्ति का प्रदर्शन किसी को महान नहीं बनाता। महानता इस बात में है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दुनिया दें जहाँ बारूद की गंध नहीं, बल्कि भाईचारे की मिठास हो। एक बार और अमेरिका वियतनाम और अफगानिस्तान में जाकर अपना अंजाम देख चुका है। बाद में बहुत कुछ गंवाकर वहां से भाग आया। ये ईरान है। ये देश के गांव वाले, युवाओं और बच्चों ने भी अब शस्त्रों से दोस्ती कर ली है। हथियार संधाल लिए हैं। अमेरिका के दो हेलिकॉप्टर को मार गिराने वाला एक मामूली गडरिया है। इस गडरिए को तो युद्ध कला भी नहीं आती। सिर्फ इतना जानता है कि ये हेलिकॉप्टर हमलावर अमेरिका के है। जिस देश की जनता इतनी जुझारू और लड़ाका हो, जिसके गडरिये अमेरिका जैसे देश के दो-दो आधुनिकतम हेलिकॉप्टर गिरा दें, उसे हराना संभव नहीं।

आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें युद्ध के उन्माद को रोकना होगा। नहीं रोका, तो वह दिन दूर नहीं जब %ईंसान% तो बचेगा, लेकिन उसके भीतर की %ईंसानियत% पूरी तरह दफन हो चुकी होगी। हमें यह समझना होगा कि धरती पर सहरदें हमने खींची हैं, कुदरत ने नहीं। शांति की मेज़ पर बैठकर बात करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। वक्त आ गया है कि हम हथियारों की होड़ को छोड़कर मानवता की जोड़ पर ध्यान दें। वरना इतिहास हमें उन लोगों के रूप में याद रखेगा, जिनके पास सब कुछ था, बस एक-दूसरे के लिए दया और प्रेम नहीं था।

युद्धविराम पर सहमति स्वागतयोग्य

शुभम कुमार

अमेरिका-इसाइल और ईरान के बीच पिछले करीब चालीस दिनों से चल रहे युद्ध में चार हजार से अधिक लोगों के मारे जाने और वैश्विक तेल व गैस के स्रोत खाड़ी क्षेत्र को अरबों डॉलर के नुकसान के बाद, दोनों पक्षों के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर जो सहमति बनी है, वह राहत देने वाली है। लेकिन, इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान और कुवैत द्वारा एक-दूसरे को निशाना बनाने की जो खबरें मिली हैं, उससे यही महसूस होता है कि शांति की इस घोषणा की असल परीक्षा अभी होनी बाकी है।

यह आशंका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ही दिन पहले ट्रंप ने ईरान की सभ्यता के अंत की धमकी दी थी और फिर घटनाक्रमों का नाटकीय मोड़ युद्धविराम के रूप में सामने आया। फिर, हम पूर्व में इसाइल व फलस्तीन के बीच भी कई असफल युद्धविराम देख चुके हैं। ऐसे में, तो यही लगता है कि अगर तीनों पक्ष आने वाले दिनों में खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं, तभी प्रस्तावित इस्लामाबाद वार्ता सकारात्मक माहौल में शुरू हो सकती है और तभी यह स्पष्ट संकेत मिल सकेगा कि इन देशों में शांति की कोई वास्तविक इच्छा है भी या नहीं।

इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम कूटनीतिक मोड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी देखने को मिला, जहां होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव को रूस व चीन ने वीटो कर दिया, जो वैश्विक शक्ति संतुलन की गहरी दरारों को ही उजागर करता है। एक ओर पश्चिमी देश हैं, जो होर्मुज को खुला रखने और ईरान पर दबाव बनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरी ओर रूस व चीन हैं, जो खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हैं। अमेरिका व ईरान के बीच



युद्धविराम के संदर्भ में यह विभाजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

जाहिर है कि जब वैश्विक शक्तियां ही एकमत नहीं हैं, तो स्थायी शांति की राह सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। इसाइल पहले ही लेबनान को निशाना बनाना जारी रखने की बात कह चुका है। जाहिर है कि यह पश्चिम एशियाई संकट का पूर्ण अंत नहीं है, फिर भी एक अंतहीन प्रतीत हो रहे युद्ध का वार्ता की जमीन पर उतरना स्वागतयोग्य है। अब पूरी दुनिया का ध्यान निस्संदेह इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता पर केंद्रित है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों ही पक्ष अपने रुख में थोड़ी ढील देने को तैयार हैं।

इतिहास गवाह है कि कई बार पक्ष इस तरह के विराम का इस्तेमाल अपनी सैन्य तैयारी मजबूत करने के लिए करते हैं। ऐसे में, इस युद्धविराम को रणनीतिक विराम बनने से रोकना होगा। अगर संघम और ईमानदारी के साथ वार्ताएं टोस दिशा में बढ़ें हैं, तभी यह विराम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

भारत को विश्वगुरु बनाना ही आर.एस.एस. का उद्देश्य

सुखदेव वशिष्ठ

‘शाखा’ जैसी अद्वितीय प्रणाली के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण का कार्य संघ करता है। इसी से लाखों स्वयंसेवक तैयार हुए हैं, जिनके जीवन के आदर्श व्यवहार से समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखता है। संघ की कार्यपद्धति अन्य संगठनों से भिन्न और विशिष्ट है। बाल स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक, सभी एक ही आदेश पर कार्य करते हैं। शाखा में होने वाले छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुशासन और संस्कार विकसित होते हैं। संघ के साथ ही समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों ने 40 से

अधिक संगठनों, जैसे ए.बी.वी.पी., लघु उद्योग भारती, सेवा भारती, विद्या भारती की स्थापना की, जो अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये सभी स्वतंत्र, स्वायत्त और स्वावलंबी संगठन हैं। भारत को पुनः ‘विश्वगुरु’ के स्थान पर प्रतिष्ठित कर भारत माता को परम वैभव पर ले जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

आर.एस.एस. के पहले चार प्रचारक = 1925 में संगठन के रूप में आकार लेने पर आर.एस.एस. के आद्य सरसंघचालक डा. हेडगेवार के सामने चुनौती थी कि संघ के विचारों का देशभर में प्रचार-प्रसार कैसे किया जाए। उन्हें समर्पित, पूर्णकालिक और संघ की भावना में दीक्षित कार्यकर्त्ताओं की तलाश थी। प्राचीन समय में जैसे ऋषि-महर्षि परम्परा थी, जो जीवन प्रणाली का अध्ययन कर अलग-अलग समय पर मनुष्य जीवन में आने वाली समस्या का हल प्राणी मात्र को देते थे, उसी प्रकार प्रचारक भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में मार्गदर्शन करते हैं। इस परम्परा में पहले 4 प्रचारक थे बाबा साहब आटे, दादा राव परमार्थ, रामभाऊ जमगडे और गोपाल राव येरकुंटवार।

2 वर्ष तक प्रशिक्षण के बाद 1929 में डा. केशव



बलिराम हेडगेवार ने प्रचारक व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की शुरुआत की। 1930 में जब डा. हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जंगल सत्याग्रह में भाग लेने पहुंचे तो सरसंघचालक के पद से इस्तीफा दिया। डा. परांजपे को नया सरसंघचालक बनाया गया। डा. हेडगेवार को पता था कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। 1931 में बाबा साहब आटे को डा. हेडगेवार ने जेल से बाहर आने के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बनाने के लिए चुना। इस तरह इन चारों को संघ की पहली प्रचारक टोली के तौर पर जाना जाता है। इनमें बाबा साहब आटे को प्रथम प्रचारक माना जाता है। संघ के पहले पूर्णकालिक प्रचारकों की दीक्षा के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम नागपुर में रखा गया, जहां प्रमुख स्वयंसेवक उपस्थित थे। उसी कार्यक्रम में डा. हेडगेवार का छोटा सा सम्बोधन हुआ, जिसमें संगठन का संकल्प और प्रचारकों का जीवन साधुओं की तरह होना चाहिए, इसी पर उनका जोर था। उसके बाद उनके केन्द्र बताए गए कि उनको प्रचार के लिए किस शहर या प्रांत में जाना है।

उत्तर-पूर्व में ‘संघ के बीच’ बोने वाले पहले प्रचारक = दादादाव परमार्थ यानी गोविंद सीताराम परमार्थ नागपुर के रहने वाले थे। 10वीं की परीक्षा की उत्तरपुस्तिका में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अध्यापकों ने उन्हें फेल कर दिया, अतः वह पढ़ाई छोड़कर डा. हेडगेवार

के साथ जुड़े और स्वयंसेवक बन गए। 1930 के जंगल सत्याग्रह में डा. हेडगेवार के साथ गए और जेल भी गए। बीमार पड़े तो जेल में डा. हेडगेवार ने ही उनकी देखभाल की थी। उत्तर पूर्व में संघ का कार्य विस्तार करने वाले वह पहले प्रचारक थे।

भविष्य के प्रचारकों को जोड़ने वाले गोपाल राव येरकुंटवार = गोपाल राव येरकुंटवार ने उस दौर में जितने समर्पित प्रचारकों को तैयार किया, शायद ही किसी ने किया होगा। उनमें से एक थे भास्कर राव कलाम्बी, जिन्हें वनवासी कल्याण आश्रम के काम की शुरु करने का श्रेय जाता है। पंजाब में शुरुआत में संघ पताका फहराने वाल मोरेश्वर राघव या मोरुभाई मुंजे को भी गोपाल राव लेकर आए थे। इन सभी प्रचारकों के नाम संघ के इतिहास में कई तरह की उपलब्धियां दर्ज हैं। केशव आटे ने तो 33 श्लोक का एक ‘भारतभक्ति श्रौत’ रच डाला था। उनका दशकों तक भारत के इतिहास के पुनर्लेखन पर काम चलता रहा। आटे ने कभी अपने पुत्र से लिखकर ‘दासबोध’ और टाइप करके वीर सावरकर की किताब ‘1857 स्वातंत्र्य समर’ अनेक नवयुवकों को उपलब्ध करवाई थी।

आर.एस.एस. के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत जी के शब्दों में, “हम लोग, अपनी दृष्टि से विचार करके जो अच्छा लगता है, वह बोल सकते हैं। जो खराब लगता है, वह भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलने के पीछे कोई विरोध की भावना नहीं है। संघ न किसी विरोध में चलता है और न किसी बैर भाव से। ‘न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।’ और दोस्ती कहें तो सब अपने हैं। सबके प्रति प्रेम है। उस प्रेम के आधार पर और स्वयंसेवकों की निष्ठा, तपस्या के आधार पर हम यहां तक पहुंचे हैं। कितने बड़े त्याग हुए, कितने बड़े बलिदान हुए, उस पर हम खड़े हैं। यह हम जानते हैं। उनके प्रति मन में जो भाव है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। संघ को हमको आगे ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि भारत को खड़ा करना है।”

बंगाल चुनाव : एसआईआर डाल सकता है कई सीटों पर प्रभाव

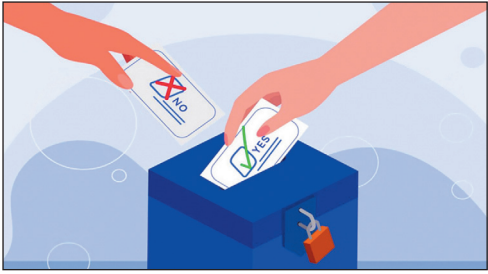
सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस चरण के मतदाता सूची में कोई और नाम शामिल नहीं किया जाएगा। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद मतदाता सूची कानून के अनुसार आखिरी हो चुकी है। गौरतलब है कि 294 सदस्यीय विधानसभा की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। राज्य की शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए मतदाता सूची को नामांकन की अंतिम तिथि के बाद 9 अप्रैल को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अब किसी भी बदलाव का फैसला उच्चतम न्यायालय के संभावित निर्देशों पर निर्भर करेगा। एसआईआर मामले पर उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद 28 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में 63 लाख 66 हजार 952 मतदाताओं का नाम बाद दे दिया गया था। 60 लाख 6 हजार 675 विवेचनाधीन मतदाता थे। दर्जन भर सूचियों के प्रकाशित होने के बाद न्यायिक जांच के दायरे में आए लगभग 45.22 प्रतिशत नाम हटा दिए गए। वहीं, इस श्रेणी के 32.68 लाख से अधिक मतदाताओं को बरकरार रखते हुए अंतिम सूची में शामिल किया गया है।

एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से 90 लाख 83 हजार 345 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई जांच में इन 60 लाख 6 हजार 675 विवेचनाधीन मतदाताओं में से 27 लाख 16 हजार 393 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के अंतिम मतदाता आधार की घोषणा अभी बाकी है।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक विवेचनाधीन नाम मुस्लिम बहुल जिलों में हटाए गए हैं।



टॉप थ्री में बांग्लादेश की सीमा से लगे तीनों मुस्लिम बहुल जिले हैं और टॉप में मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में न्यायिक जांच में 11.01 लाख नामों में से 4 लाख 55 हजार 137 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस तरह, जिले में न्यायिक जांच के तहत हटाए गए नामों की संख्या लगभग 41.33 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर उत्तर 24 परगना है जहां 3 लाख 25 हजार 666 नाम हटाये गए हैं। तीसरे नंबर पर मालदा है जहां 2 लाख 39 हजार 375 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। न्यायिक जांच में उत्तर 24 परगना जिला दूसरे नंबर पर है लेकिन कुल हटाये गए मतदाताओं की तालिका में टॉप पर है। टॉप टेन जिला पर यदि नजर डालें तो उत्तर 24 परगना में 12 लाख 60 हजार 96 लोगों का नाम कटा है।

दक्षिण 24 परगना में 10 लाख 91 हजार 98, मुर्शिदाबाद में 7 लाख 48 हजार 959, हावड़ा में 5 लाख 95 हजार 916, नदिया में 4 लाख 87 हजार 565, हुगली में 4 लाख 68 हजार 939, मालदा में 4 लाख 59 हजार 530, उत्तर कोलकाता में 4 लाख 47 हजार 541, पूर्वी बर्दवान में 4 लाख 35 हजार 864 और पश्चिम बर्दवान में 3 लाख 94 हजार 325 मतदाताओं का नाम सूची से कट गया है।

गौरतलब है कि आंकड़ों के अनुसार, नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों में सुनवाई के बाद हटाए गए सदस्यों की संख्या क्रमशः 77.86 प्रतिशत और 55.08 प्रतिशत है। इन

दोनों जिलों में हिंदू नामशुद्ध मतुआ समुदाय के सदस्यों की अच्छी खासी संख्या है। केंद्र में इस समुदाय के शांतनु ठाकुर मंत्री भी हैं।

वहीं, कोलकाता दक्षिण में 28,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। सुनवाई के दौरान हटाए गए नामों का प्रतिशत 36.19 प्रतिशत रहा। कोलकाता उत्तर में जांच के दायरे में आए करीब 39,000 मतदाता मतदान के लिए अयोग्य पाए गए, जिससे वहां हटाए गए नामों का प्रतिशत लगभग 64 प्रतिशत रहा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर%25 में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मतदाताओं की संख्या का लगभग 8.3 प्रतिशत यानी 63.66 लाख नाम हटा दिए गए, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर करीब 7.04 करोड़ रह गया है। 7.04 करोड़ के मतदाता आधार में 60.06 लाख से अधिक मतदाता ऐसे थे, जिन्हें विवेचनाधीन श्रेणी में रखा गया था।

अंतिम मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं के पास उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों में जाने का विकल्प है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों द्वारा योग्य पाए गए मतदाता आगामी चुनावों में अपने मतों द्वारा इससेमाल कर पाएंगे या नहीं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से की गई है। पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब जिला-वार आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं।

विवेचनाधीन 60.06 लाख मतदाताओं में से 59.84 लाख का डेटा सार्वजनिक किया जा चुका है, जबकि शेष 22,163 मामलों का निस्तारण हो चुका है, लेकिन अभी ई-हस्ताक्षर होना बाकी है। ई-हस्ताक्षर सहित समस्त लॉबिग औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नाम हटाने और जोड़ने के आंकड़ों में मामूली बदलाव संभव है।

भारत की न्यूक्लियर पाँवर देख काँपा चीन

नीरज कुमार दुवे

भारत का परमाणु सपना आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दशकों की प्रतीक्षा, संघर्ष और वैज्ञानिक जिद के बाद कलपक्कम में तैयार प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और सामरिक स्वतंत्रता का उद्घोष बन गया है। यह वह क्षण है जब भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को नई दिशा दे रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति भी मजबूत कर रहा है। कलपक्कम में स्थापित यह रिएक्टर देश के तीन चरण वाले परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम पड़ाव है। भारत के पास यूरेनियम की सीमित उपलब्धता है, लेकिन थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि इस रिएक्टर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल बिजली पैदा नहीं करता, बल्कि प्लूटोनियम और भविष्य के लिए जरूरी ईंधन भी तैयार करता है। यही इसे साधारण रिएक्टर से अलग और रणनीतिक रूप से बेहद ताकतवर बनाता है। इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी ब्रीडिंग क्षमता है, यानी वह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करता है। इसमें मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का इस्तेमाल होता है और सोडियम कूलिंग प्रणाली इसे तेज और प्रभावी बनाती है। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जिनके पास उन्नत परमाणु क्षमता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। यह परियोजना लंबे समय तक देरी, लागत वृद्धि और तकनीकी चुनौतियों से जूझती रही। शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक खर्च हुआ और समय सीमा भी कई बार आगे बढ़ी। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की लगातार मेहनत ने इस परियोजना को आखिरकार सफलता के करीब पहुंचा दिया। यहां सबसे अहम

सवाल यह है कि इस उपलब्धि का सामरिक महत्व क्या है। इसका जवाब सीधा है, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता। आज दुनिया ऊर्जा संकट, तेल और गैस की राजनीति और वैश्विक अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत का यह कदम उसे बाहरी निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। परमाणु ऊर्जा केवल बिजली का स्रोत नहीं है, यह शक्ति संतुलन का आधार भी है। जिन देशों के पास उन्नत परमाणु तकनीक होती है, वह वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह रिएक्टर भारत को उसी श्रेणी में पहुंचाने का माध्यम है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि भारत की रक्षा और तकनीकी क्षमता भी मजबूत होगी। रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह परियोजना भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। थोरियम आधारित कार्यक्रम भारत को आने वाले दशकों तक स्थायी ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। इससे न केवल उद्योगों को बल मिलेगा, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम भी सशक्त होंगे। इसके अलावा, यह परियोजना भारत की वैज्ञानिक क्षमता को भी प्रमाण है। यह संदेश साफ है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता भी है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है, जो देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाएगा। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सुरक्षा, अप्रसिद्ध प्रबंधन और लागत नियंत्रण जैसे मुद्दे अब भी अहम हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यह उपलब्धि भारत के लिए ऐतिहासिक है। देखा जाये तो यह रिएक्टर केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक विचार है, एक विजय है। यह उस भारत की तस्वीर पेश करता है जो अपने संसाधनों का सही उपयोग करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

बगल से जब कोई लंबी कार 150 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती है, तो आपके मन में विचार नहीं आता कि इतनी स्पीड कैसे। जमाना हार्डटेक है और इस जमाने में रोजाना नए प्रयोग हो रहे हैं, जो कारों की दुनिया को और हार्डटेक कर रहे हैं। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने अपनी स्पोर्ट्स कसेट कार जीना यानी जियोमेट्री एंड फंक्शंस इन एड्रेशंस का पर्दापण किया, तो अन्य कार निर्माता कंपनियों के साथ-साथ पूरी दुनिया के लोग हेरान रह गए। यह एक ऐसी कार है जिसका शोप और लुक हर रोज बदला जा सकता है। इसकी बॉडी किसी तरह के मेटल या प्लास्टिक की बनी हुई नहीं

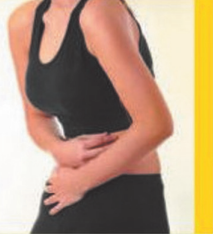
रोज शोप और लुक बदलती कार...

तकनीक पहली बार बीएमडब्ल्यू ने इस्तेमाल की है। जीना को बनाने में प्लेक्सिबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जीना के एक्सटीरियर और इंटीरियर का हर हिस्सा प्लेक्सिबल है। इस तकनीक के तहत कार के फ़ैब्रिक रिक्न के नीच मूवेबल मेटल वायर्स लगाए गए हैं और इन्ही वायर्स को एडजस्ट करके कार की शोप को बदला सकता है। मेटल फ़्रेम एडजस्ट करने के लिए एक बटन दबाना होता है और इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक ड्रिवाइस यह काम कर देती है।

है बल्कि इसे बनाने में फ़ैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इस कार को मनपसंद लुक देना बेहद आसान है। यह कार अपने लुक को बदलने में केवल कुछ मिनटों में काम कर लेती है।

डिब्बाबंद चीजों पर जरूरी है अच्छी लेबलिंग

डिब्बाबंद खाद्यपदार्थों में नमक की अधिक मात्रा लोगों को रोगों का शिकार बना रही है। शोध के अनुसार ब्रिटेन में होने वाले 14 प्रतिशत पेट के कैंसर के मामलों को नमक का कम सेवन करके रोका जा सकता है। ब्रिटेन में प्रत्येक व्यक्ति 8.6 ग्राम नमक खाता है, व्यक्ति को सिर्फ 6 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर उचित लेबलिंग और तत्वों की स्पष्ट जानकारी कई रोगों से बचा सकती है।



स्वस्थ रहना है तो सोना सीखिए

हर किसी के सोने की खास मुद्रा यानी स्लीपिंग पोजिशन होती है। कोई पेट के बल सोता है, कोई पीठ के तो कोई करवट लिए। कुछ लोग बिस्तर पर लेटते तो सामान्य पोजिशन में हैं, पर जैसे-जैसे नींद गहराती है, उनकी मुद्रा तरह-तरह के आकार ले लेती है। बात रोचक भले ही लगे, मगर मत भूलिए कि ये मुद्राएं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। कुछ आपको सेहत लाभ देती हैं तो कुछ आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकती हैं।

शरीर को पुन सक्रिय और स्वस्थ बनाने के लिए नींद बेहद जरूरी है, जिसे ‘रेस्टोरेशन एंड रिकवरी थ्योरी ऑफ स्लीप’ कहते हैं। कोई पेट के बल सोता है, कोई पीठ के तो कोई करवट लिए, मगर कुछ मुद्राएं इससे भी अलग और रोचक होती हैं। हर व्यक्ति की

सोने की खास मुद्रा होती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि सोने के समय आपके शरीर की हर मुद्रा आपकी मनोदशा उजागर करती है। यों तो हर उम्र की खास मुद्राएं होती हैं, मगर युवा अवस्था में सबसे अधिक निद्रा मुद्राएं होती हैं। यह मुद्राएं शरीर को प्रभावित करती



विपरीत होने के कारण यह गले की मांसपेशियों को झोल देने से रोकती है और खरोंटे नहीं आते, मगर यह मुद्रा गले को अवरुद्ध यानी ‘चोक’ भी कर सकती है।

पिलो होल्डिंग स्लीपिंग पोजिशन

इसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटता है, मगर अपने सोने पर दोनों हाथों से तकिया या फिर जाड़ों में रजाई दबाए रहता है। यह मुद्रा तल्लीनता का भाव जगाती है। जो युवा अपने अध्ययन के प्रति समर्पित हैं, वह अकसर ऐसे ही सोते हैं। चिकित्सीय आधार पर यह बेहतर नींद दिलाने वाली मुद्रा है। अगर आप ‘इनसोमेनिया’ यानी अनिद्रा के शिकार हैं तो यह बेहतर मुद्रा है।

चेन गेंग पोजिशन

एक अन्य मुद्रा है कड़ी मुद्रा या ‘चेन गेंग पोजिशन’। इसमें सोने वाले हाथ पैर की एक कैंची-सी बना

हैं और सीधे व्यक्ति के तन और मन की सेहत से जुड़ी होती हैं। यहां तक कि शरीर में पनपते कुछ रोग विशेष निद्रा मुद्रा के कारण गंभीर अवस्था में भी आ जाते हैं तो वहीं कुछ निद्रा मुद्राएं शरीर को आराम पहुंचा कर स्वास्थ्य लाभ कराती हैं।

डालते हैं यानी हाथ ऊपर की ओर एक कड़ी बनाते हैं तो पैर नीचे की ओर। इस प्रकार सोने वाले ‘फोबिया’ यानी भय से पीड़ित होते हैं। यह मुद्रा कुंवारी लड़कियों में अधिक पाई जाती है। चिकित्सीय विश्लेषण के अनुसार यह भय एक ग्रंथि बन मानसिक रोग पनपाता है, अतः-इस मुद्रा से बचना चाहिए।

सिक्स पोजिशन

सिक्स पोजिशन यानी रहस्यमयी मुद्रा। इसमें व्यक्ति असाधारण रूप से घुटने के सहारे नितम्ब उठाए रहता है तथा सिर को हथेली से थामे रहता है मानो दण्डवत प्रणाम कर रहा हो। हालांकि यह बच्चों की सामान्य निद्रा मुद्रा है, मगर युवाओं को भी इस मुद्रा में सोते देखा जा सकता है। यह उदर विकार को दर्शाती है। पूरे शरीर को मोड़ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत रख कर सो जाना आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करता है, अतः-इस मुद्रा से बचें।

स्वास्तिक मुद्रा

यह जागृतावस्था और स्वप्नावस्था का सीधा सामंजस्य दर्शाती है। इसमें पेट के बल सोते हैं। दाहिना हाथ ऊपर की ओर और बायां हाथ नीचे की ओर रहता है। इसी तरह दायां पैर घुटने से मुड़ कर ऊपर की ओर रहता है और बायां सीधा रहता है। इस तरह सोने वाले लोग पूरे पलंग पर हावी रहते हैं। इस मुद्रा में उदर में समाए अंग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाते हैं, अतः-विभिन्न विकारों की संभावना रहती है। यह मुद्रा बहुत कम संभव होती है और स्वयं बदल जाती है।

बदलती रहती है निद्रा मुद्राएं



सोने की यह मुद्राएं यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पूरे जीवन में व्यक्ति न केवल मुद्रा बदलते हैं, बल्कि उसके अनुसार उनके रोग भी बदल जाते हैं और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रोचक पहलू यह है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं जान पाते कि वह किन-किन मुद्राओं में सोते हैं और उनकी कौन-सी मुद्रा कब बदल जाती है। इसी प्रकार जो मुद्रा वह बहुत पहले लिया करते थे, वह फिर आ जाती है या फिर जो उनकी प्रिय मुद्रा थी, वह अचानक बदल जाती है और उसकी जगह नई मुद्रा आ जाती है। रोचक बात यह है कि नई मुद्रा पुनर्नी पर इस हद तक हावी हो जाती है कि वही प्रिय लगने लगती है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अपने से जुड़ी मुद्राएं स्वयं जान कर या दूसरों से पृष्ठ उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी संपूर्ण जानकारी लेते हुए उनका अपने से जोड़ कर अध्ययन कीजिए। अगर कुछ दुःखदायी, कष्टदायक और रोगवाहक मुद्राएं आप में अब भी पनप रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें।

बहुत कुछ होता है नींद में

वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि जब हम सोते हैं तो एकदम भिन्न दशाओं से गुजरते हैं। स्वेदी यंत्रों द्वारा प्रयोगशाला में इसे समझा गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहली दशा स्लो वेव स्लीप यानी नींद की धीमी गति प्रदर्शित करती है। तर्गतित विद्युत प्रक्रिया की यह सबसे धीमी गति पूरे मस्तिष्क से गुजरती है और उसे तरोताजा करती है। यानी यह अवस्था है रेपिड आइ मूवमेंट, जिसे रैम पोजिशन भी कहते हैं। इस अवस्था में बंद पलकों में आंख की पुतली तेजी से चलती है। हैरानी की बात तो यह है कि यह मस्तिष्क को झकझोर देती है यानी यह अवस्था जागृतावस्था जैसी ही है। पहली बार शोधकर्ता ने नींद की इस छिपी प्रक्रिया से पर्दा उठाया और पहली बार नींद को समझा। शोधकर्ता ने पता किया कि रैम अवस्था नींद के उस भाग को बताती है, जो अपने आप में पूर्ण गतिशील है। हम जागृतावस्था में आंखों को इतनी तेज गति से नहीं चलाते, जितनी कि रैम अवस्था में चलाते हैं। यह दशा मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखती है। रिपोर्ट बताती है कि नींद आना शरीर की अंतर्गामी जैविक क्रिया है। इस समय शरीर की सामान्य क्रियाएं अपेक्षाकृत धीमी पड़ जाती हैं। मगर रहस्यपूर्ण बात यह है कि सोते समय हमारा पाचनतंत्र काफी सक्रिय हो जाता है।

रेसिपी



विधि

एक बर्तन में बेसन, पुदीना हरी मिर्च का पेस्ट नमक और अजवाइन मिव्स करें। थोड़ा पानी डालें। अच्छी तरह से मिलाकर गूंध लें। इसके गून्हे बना लें। पानी में उबालें। पक जाने पर गून्हे को मनचाहे आकार में काट लें। तेल में फ्राई करें। चाट मसाला छिड़कें। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। आप चाहें तो प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ भी इन गून्हे का स्वाद ले सकती हैं।

पुदीना गट्टा

सामग्री

बेसन दो कटोरी, तीन बड़े चम्मच पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, सरसों का तेल, चाट मसाला, नींबू

चना दाल खीर

सामग्री

दूध-2 लीटर, चने की धुली दाल-1/4 कटोरी, बारीक कटी मेवा-एक छोटी कटोरी, चीनी-100 ग्राम, किंसा कच्चा नारियल-2 बड़ा चम्मच, मिल्क पाउडर-एक कटोरी, शुद्ध घी-एक छोटा चम्मच, इलायची पाउडर-1/4 छोटा चम्मच

विधि

दूध को गरम करें। उबाल आने के बाद 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। चने की दाल को धोकर गरम घी में 3-4 मिनट भूनें और उबलते दूध में डालें। दाल को अच्छी तरह गलने तक पकाएं। गैस बंद करके गर्म दूध में ही मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, मेवा और चीनी डालकर चलाएं। कच्चा नारियल तवे पर भूनें और हल्का बादामी हो जाने पर खीर के ऊपर डालें। स्वादिष्ट खीर सर्व करें।

अस्पतालों और रेडियो थैरेपी सेंटर्स में बढ़ी फिजिसिस्ट की मांग

रेडिएशन फिजिक्स में बेहतर कैरियर का विकल्प

फिजिक्स यानि भौतिक शास्त्र के तहत ऊर्जा के रूपांतरण एवं उसके द्रव्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्थान, काल, गति, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा एवं ध्वनि के गुणों तथा एक-दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा किसी न किसी रूप में जरूरी है और धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका अध्ययन भी बेहद मायने रखता है। रेडिएशन भी एक तरह की ऊर्जा है। इसे ऐसी ऊर्जा माना जाता है जो किसी माध्यम अथवा स्थान से गुजरते हुए किसी अन्य तत्व में सोख ली जाती है। इसके तहत चिकित्सा क्षेत्र में रेडिएशन थैरेपी के उपयोग के लिए रेडिएशन की सुरक्षित मात्रा का आकलन किया जाता है। रेडिएशन फिजिक्स के क्षेत्र में कैरियर की ओर संभावनाएं मौजूद हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आप खुद को कैसे तैयार करें...?



नेचर ऑफ वर्क

निर्माण, न्यूक्लियर एनर्जी तथा अत्याधुनिक चिकित्सा जांच-पड़ताल एवं उपचार संभव हो सका है। वैसे भी इस विषय में समग्र भौतिकी की अहम भूमिका है जिस कारण इसमें फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कैमिस्ट या मेडिकल फील्ड के लोग काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग काफी ज्यादा है और बेहतरीन पारिश्रमिक वाले पदों पर नौकरियां भी खूब उपलब्ध हैं।

आपॉर्चुनिटीज...

यह एक बढ़िया कैरियर तो है ही साथ ही साथ बेहद चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि इसमें ईंसानों की रक्षा तथा रेडिएशन द्वारा उनके कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन पर ही होती है। हाल के सालों में अस्पतालों, रेडियो थैरेपी सेंटरों तथा कुछ विशेष उद्योगों एवं संस्थानों में मेडिकल फिजिसिस्ट की मांग काफी बढ़ गई है। दिशा-निर्देशों के तहत रेडियो थैरेपी सेंटर या अस्पताल में प्रशिक्षित मेडिकल फिजिसिस्ट को नियुक्त करना अनिवार्य है।

लाइटिंग सही रखें और हरियाली भी लगाएं

कई लोग कहते हैं कि उनके डेस्क पर लगी लाइट या तो बहुत ज्यादा तेज होती है या फिर बहुत धीमी। यदि आपको भी यह समस्या है तो आप अपने डेस्क पर अच्छा-सा लैंप लगाकर उस लाइट को सही कर सकती हैं। हरा रंग आंखों के लिए अच्छा माना जाता है इसलिए अपने ऑफिस में थोड़ी-सी हरियाली भी लगाएं। इसके लिए आप कोई छोटा-सा ग्रीन प्लांट अपनी डेस्क पर रख सकती हैं। अपनी ऑफिस डेस्क को रंगीन बनाने के लिए आपको रंगीन स्टेशनरी खरीदनी चाहिए, जिससे आपका ऑफिस डेस्क हमेशा खिला-खिला लगे। हर ऑफिस में सॉफ्ट बोर्ड होता है जिसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए।

टार्गेट का प्रिंट आउट

जब आप अपनी ऑफिस डेस्क को सजा रहे हों तो वह सजावट न केवल आपके काम को बल बढ़ावा ही दे, बल्कि आपके काम को शो भी करें, ऐसा आपका मकसद होना चाहिए। अपने टार्गेट का एक प्रिंट आउट निकालकर अपनी डेस्क के सॉफ्ट बोर्ड पर लगाएं। इससे आपके दिमाग में हमेशा वही काम रहेंगे जो आप करना चाहते हैं और आपका यह कदम आपकी सैलरी बढ़ाने में भी मदद करेगा। अपनी ऑफिस डेस्क को मस्त बनाने के लिए उस पर एक फंकी पेन स्टैंड रख सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि कई लोगों को ऑफिस का काम क्यों बोरिंग लगता है, क्योंकि उनके ऑफिस डेस्क पर चारों ओर दुनिया भर का सामान बिखरा पड़ा होता है और वह सजावा नहीं होता। यदि आप अपने घर से ज्यादा समय अपने ऑफिस में बिताते हैं तो यह जरूरी है कि ऑफिस डेस्क को ऐसा सजा दिया जाए कि वहां पर बैठकर काम करने का दिल करे। ऑफिस डेस्क को सजाने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि वहां पर किन-किन चीजों को बचाने की आवश्यकता है। कई लोगों को लगता है उनकी डेस्क पर लाइटिंग को बदलने की आवश्यकता है तो वे अपनी डेस्क पर लैंप लगा लेते हैं। यदि आप भी अपनी ऑफिस डेस्क को सजाने की सोच रहे हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। ऑफिस डेस्क को व्यवस्थित रखने का ये तरीका आपकी सैलरी बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है।



साफ-सफाई का रखें ध्यान...

यदि आपकी ऑफिस डेस्क फालतू सामान से घिरी और बिखरी हुई है तो फिर आप उसे चाहे जितना मज्जी सजा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा अपनी ऑफिस डेस्क को साफ-सुथरा रखें और जिन चीजों की आवश्यकता न हो उन्हें निकाल दें या फिर ड्राअर में रख लें।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ

नईदिल्ली। बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार के राज्यसभा में पदभार ग्रहण करने के साथ ही बिहार में उनका लंबा कार्यकाल समाप्त हो गया। सत्तारूढ़ एनडीए अब 14 अप्रैल को राज्य के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। नीतीश कुमार ने राज्य विधान परिषद के सदस्य पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 30 मार्च को पद छोड़ दिया था। जेडीयू प्रमुख 16 मार्च को उच्च सदन के लिए चुने गए थे और उन्हें चुनाव के बाद निर्धारित 14 दिनों के भीतर एमएलसी पद से इस्तीफा देना आवश्यक था। कुमार बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और हवाई अड्डे पर जद(यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया।

पासपोर्ट विवाद : पवन खेड़ा को कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

हैदराबाद। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय से राहत मिली, जिसने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दायर एक मामले में एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। रिनिकी भुयान शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति के. सुजाना ने सुनाया, जिन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता (खेड़ा) को संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। खेड़ा के खिलाफ मामला असम पुलिस ने तब दर्ज किया था जब उन्होंने दावा किया था कि भुयान के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अचोषित संपत्ति है। इस सप्ताह की शुरुआत में असम पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी तलाशी ली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था।

ओवैसी ने बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ तोड़ा गठबंधन

हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। यह कदम तब उठाया गया, जब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने एक कथित रिंग वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कबीर को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों और बीजेपी के साथ अपने %संबंधों% को लेकर विवादित दावे करते हुए दिखाया गया है। कबीर, जिन्हें पिछले साल के आखिर में तृणमूल से निर्लंबित कर दिया गया था और जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी एजेयूपी बनाई, ने इस वीडियो को एआई-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया) बताकर खारिज कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ताधारी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बहु-करोड़ की योजना का हिस्सा था, जिसका मकसद आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराना था।

तमिलनाडु झुकेगा नहीं, दिल्ली को स्टालिन का सीधा संदेश

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु झुकेगा नहीं और राज्य के अधिकारों या संघवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार गरिमा और आत्मसम्मान के लिए खड़ी है और किसी भी प्रकार के थोपे जाने के खिलाफ है, साथ ही जनहितैषी, कल्याणकारी और समावेशी शासन के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी ये टिप्पणियां तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले आई हैं, जिनके लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी। एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने लिखा कि तमिलनाडु झुकेगा नहीं। राज्य के अधिकारों या संघवाद पर कोई समझौता नहीं। गरिमा और आत्मसम्मान के लिए हां। थोपे जाने के खिलाफ। जन-केंद्रित, कल्याणकारी और समावेशी शासन के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध। स्टालिन ने एक भारतीय दैनिक समाचार पत्र में दिए अपने साक्षात्कार की एक क्लिपिंग भी साझा की।

9 मुस्लिम संगठनों का एनडीए गठबंधन को बिना शर्त समर्थन

चेन्नई। दक्षिण भारत दरगाह मस्जिद एसोसिएशन, जिसके वरिष्ठ सदस्य एमजीएफए जाफर अली हैं, ने तमिलनाडु उर्दू मुस्लिम विकास संगठन और अन्य सुफी सुन्नी समूहों सहित आठ अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी से मुलाकात की और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को अपना निःशर्त समर्थन दिया। एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने मुस्लिम संगठनों को आश्वासन दिया कि एआईएडीएमके सरकार तमिलनाडु राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से सुफी सुन्नी मुसलमानों का समर्थन करती रही है और कानूनी रहेगी। दक्षिण दरगाह मस्जिद एसोसिएशन ने सुन्नी मुस्लिम समुदाय की राय लिए बिना एक गैर-ताबी कच्ची मुस्लिम को धेनबारपिरी से मुख्य कार्य नियुक्त किए जाने पर निराशा व्यक्त की। इस निर्णय से तमिलनाडु के 2.3 प्रतिशत कच्ची मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी

45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, यूसीसी भी लागू होगा : शाह

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे में हैं। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे भरोसे का पत्र बताया।

उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा के माहौल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। अमित शाह के अनुसार, इस घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से जुड़ा रहे किसानों को इससे नई दिशा मिलेगी, जबकि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल है।

इसके अलावा अमित शाह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर ही सातवें वेतन आयोग और आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार का सभी योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही छह माह के अंदर ही यूसीसी भी लागू करेंगे। महिलाओं के लिए एलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार %लक्ष्मी भंडार% योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक खाते में 3 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगी।



महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को %लक्षपति दीदी% बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मंडल में महिला थाने और महिला डेस्क स्थापित करने की योजना है, ताकि महिलाओं को बेहतर और त्वरित सहायता मिल सके। यह भी कहा गया है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल न उठे और उन्हें किसी भी समय बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस न हो।

इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने की योजना है। वहीं, राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू करने का भी वादा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे।

राज्य के विकास को गति देने के लिए व्यापक योजनाओं का खाका पेश किया गया

है। इसके तहत कोलकाता मेट्रो का पूरी तरह विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाया जा सके। रेलवे परियोजनाओं को तेजी देने के लिए एक साल के भीतर 61 प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि ये परियोजनाएं विकास की मुख्य धुरी बन सकें। इसके साथ ही,

सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को 200 दिनों के भीतर हटाने का लक्ष्य तय किया गया है। नदी-नालों में पेट्रोलिंग की एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था करेंगे।

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में स्नातक पूरा करने वाले युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता देने का वादा किया गया है, ताकि वे अपने करियर की शुरुआत में आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की योजना भी शामिल है, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में मदद मिल सके।

इसके अलावा पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के कारण जिन युवाओं ने आयु सीमा पार कर ली है, उन्हें विशेष राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे उम्मीदवारों को अधिकतम पांच साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे दोबारा अवसर पा सकें। 2015 के बाद से जिन युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए भी पर्याप्त भर्ती अवसर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में देरी पर बोले जयराम रमेश

महिलाओं से पीएम मोदी को मांगनी चाहिए माफी

नईदिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चुनावी हथकंडा करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर यू-टर्न लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने इसे मोदी सरकार का यू-टर्न बताते हुए कहा कि यह विपक्ष के साथ संवाद करने की उनकी अनिच्छा और उनकी योजना बनाने की पूर्ण कमी को दिखाता है। उनकी पाखंड और भ्रामक राजनीति की कोई सीमा नहीं है।

रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री ने खुद को लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के एकमात्र चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश में मीडिया में लेख लिखना शुरू कर दिया है। दरअसल, उन्हें भारत की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को उसी वर्ष संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया



था तो कांग्रेस ने इसे 2024 से ही लागू करने की मांग की थी, लेकिन यह प्रधानमंत्री को स्वीकार्य नहीं था।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण को परिसीमन और उस जनगणना की कवायद पर निर्भर बना दिया था, जिसे वह कराने में विफल रहे और फिर कई वर्षों तक टालते रहे।

रमेश ने दावा किया, “अब जब निर्वाचन आयोग के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करने के बावजूद विधानसभा चुनावों में (भाजपा की) हार तय जरूर आ रही है तब 30 महीनों बाद प्रधानमंत्री ने अपना मन बदल दिया है। वह चाहते हैं कि हम जनगणना को भूल जाएं और जनगणना आधारित परिसीमन को इस आधार पर भूल जाएं कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा।”

उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य के बावजूद है कि उनके जनगणना पंजीयक ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के परिणाम 2027 तक

सामने आ जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, “यह एक कहानी है जो झूठ और गोलमोल बातों पर आधारित है। यह सब इस उम्मीद से किया गया है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की महिलाएं भाजपा का समर्थन करेंगी। आखिरकार, भाजपा के पास इन रण्यों में किसी अन्य मुद्दे पर कोई सार्थक विमर्श नहीं है।”

रमेश ने दावा किया, “यह मोदी सरकार का यू-टर्न है, जो विपक्ष के साथ जुड़ने की उसकी अनिच्छा और योजना की पूर्ण कमी को उजागर करता है।” उन्होंने आरोप लगाया , “प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही यू-टर्न का श्रेय लेने का दावा कर रहे हैं। उनके पाखंड और धोखे की कोई सीमा नहीं है। यह सब शासन में उनकी बड़ी विफलताओं और विदेश नीति में गंभीर झटकों को छुपाने के लिए है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि

यह पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मोदी ने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में यह भी कहा था कि यह कदम उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से भारत की सभ्यतागत विचारधारा का मार्गदर्शन किया है कि समाज सभी प्रगति करता है जब महिलाएं प्रगति करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का लेख

क्या था मुख्य संदेश?

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित कर महिला आरक्षण को करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया था। उनके लेख के प्रमुख बिंदु थे-

एकजुटता का आह्वान: प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करने की अपील की।

सभ्यतागत विचारधारा: उन्होंने कहा कि समाज सभी प्रगति करता है जब महिलाएं प्रगति करती हैं, और यह विधेयक इसी सिद्धांत की पुष्टि है।

महज विधायी प्रक्रिया नहीं: पीएम के अनुसार, यह कानून केवल कागज पर नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सभ्यतागत सोच का हिस्सा है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज की 2025-26 में बिक्री बुकिंग 16% बढ़ी

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बिक्री बुकिंग गत वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत आवासीय मांग के दम पर सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 34,171 करोड़ रुपये हो गई। बिक्री बुकिंग (प्री-सेल) के लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टीज के 2025-26 में सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी बनने की संभावना है। कंपनी ने गत वित्त वर्ष के लिए 32,500 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग का लक्ष्य रखा था जिसे उसने पार कर लिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, वित्त वर्ष 2025-26 में बुकिंग मूल्य सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 34,171 करोड़ रुपए रहा। यह 17,515 इकाइयों की बिक्री के जरिये हासिल हुआ, जिनका कुल क्षेत्रफल 2.7 करोड़ वर्ग फुट है।

स्टेल प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स का विजयी रथ रोकने उतरेगी सनराइजर्स

मोहाली। पिछले साल के अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने वाली पंजाब किंग्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब तक संघर्ष कर रही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले मैच में अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स की टीम ने जिस तरह से अभी तक प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ बारिश के कारण रद्द कर दिए गए उसके पिछले मैच में अंक बांटने से वह खुश नहीं होगी।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स में यह दिखा दिया है कि एक विजेता टीम पर दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। फिर चाहे वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 200 रन से अधिक के लक्ष्य काआसानी से पीछा करना हो या मुर्छापुर की मुश्किल पिच पर पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटन्स को हराना। केकेआर के खिलाफ इंडन गार्डेन्स में भी पंजाब किंग्स ने अच्छी शुरुआत की थी। उसके ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज किंथिर बार्टलेट ने शुरू में ही दो विकेट ले लिए थे लेकिन भारी बारिश और आंधी के कारण उसे अंक बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

पिछले सत्र में 500 से अधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर प्रभसिंघर सिंह ने टीम के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अर्रिज कैप (टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज) या पर्पल कैप (टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज) हासिल करने की होड़ के बजाय सामूहिक सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उसकी यह मानसिकता कूपर कोनली की गुजरात टाइटन्स के खिलाफ नाबाद 72 रनों की पारी और विजयकुमार वैशाक के गेंदबाजी में बढ़ते प्रभाव में स्पष्ट नजर आता है।

सैंसेक्स 918 अंक चढ़ा निफ्टी 24050 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के अंतिम ट्रेडिंग सेशन यानी शुक्रवार (10 अप्रैल) को पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुए। ऑटो स्टॉक्स के साथ बैंकिंग और इंडेक्स हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मजबूती के साथ 77,198 अंक पर खुला। जबकि गुरुवार को यह 76,631 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 77,622 अंक तक चढ़ गया था। अंत में यह 918.60 अंक या 1.20 फीसदी की बढ़त के साथ 77,550.25 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 बढ़त के साथ 23,880 पर खुला। जबकि गुरुवार को यह 23,775 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 24,074 अंक के इंट्रा-डे हाई तक गया। अंत में 275.50 अंक या 1.16 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,050 पर बंद हुआ।

गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ सफल

नईदिल्ली। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों को लेकर एक अहम उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन के तहत दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-02) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह परीक्षण सटीक ध्वन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया। आईएडीटी यानी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन का एक बेहद अहम और तकनीकी रूप से जटिल परीक्षण है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लौटेंगे, तब उनका कू मांड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति से प्रवेश करेगा।



है। 500 मेगावाट क्षमता वाले इस उन्नत रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने डिजाइन और भारतीय नाभिकीय विद्युत् निगम लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसे बनाने में 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका रही है। इस रिएक्टर को भविष्य में थोरियम-232 का उपयोग करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के विशाल थोरियम भंडार का दोहन करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

मृत्युंजय दीक्षित

पश्चिमी एशिया युद्ध और तनाव के मध्य भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली है। अब रूस के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां ऑटो मोड में परमाणु चैन रिएक्शन प्रारंभ हो गया है। यह सपना महान वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा का थी जो अब पूर्ण हुआ है।वैज्ञानिकों की यह सफलता भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देगी। यह 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर बड़ा कदम है।

अगर यह कार्य सफलता पूर्वक आगे बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा बनाने की जगह

स्वच्छ अक्षय ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत के 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रथम क्रिटिकैलिटी स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने कहा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उच्च तापीय दक्षता के साथ विश्वसनीय, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बेस लोड बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत का यह मील का पथर देश को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद पीएफबीआर ने क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर

क्या होती है क्रिटिकैलिटी- यह परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह स्थिति है जिसमें परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह रिएक्टर अब बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के द्वारा ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो गया है। क्रिटिकैलिटी प्राप्त करमा सीधे बिजली बनाना नहीं है अपितु यह उसके लिए पहली अनिवार्यता है। अब इस रिएक्टर की क्षमता और कुशलता को समझने के लिए कम क्षमता वाले कुछ परीक्षण किये जायेगे जिसके बाद इसे पावर ग्रिड से जोड़कर बिजली उत्पादन शुरू किया जा सकता है।

यह उपलब्धि मात्र एक रिएक्टर चलाने की नहीं है, इससे भारत की तमक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। इससे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कम कचरा पैदा करता है यह थोरियम और प्लूटोनियम का बेहतर उपयोग

करता है। इससे भविष्य में बिजली सस्ती होगी। देश ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूत बनेगा। भविष्य में और अधिक ऐसे रिएक्टर बनाए जा सकेंगे जो थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली बनाएंगे।

यह रिएक्टर 2004 में शुरू हुआ था लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों, देरी और लागत बढ़ने के कारण अब जाकर क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर सका है। तरल सोडियम को संचालना, सुरक्षा मानक पूरा करना और बहुत सारे परीक्षण करना असान नहीं था। इसका बजट बढ़ा किंतु सरकार का पूरा समर्थन मिलता रहा। अब यह सफलता दिखाती है कि भारत कठिन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो सकता है। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष डा. अनिल काकोदकर ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि यह भारत के तीन चरण के कार्यक्रम को नई दिशा व गति देगा।

माल पर प्रदर्शन शुल्क 200 रु से बढ़ाकर अब 600 रु प्रति शो

■ खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों को होगा व्यवस्थापन

■ सामुदायिक भवन को पुलिस कमिश्नरेट उपायुक्त पश्चिम कार्यालय के लिए दी गई



सर्कस पर 100 प्रतिशत जादूगर प्रतिशो 200 मीना बाजार पर प्रतिदिन 500 रूपए पूर्व की भांति कर लिया जाएगा। मीना बाजार प्रदर्शनी उद्योग मेला व्यापार मेला के आयोजन पर 10000 वर्ग फुट तक भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त प्रदर्शन लिया जाएगा।

यह शुल्क प्रति 10000 वर्ग फीट पर 500 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार दर निर्धारित होगा। शासकीय प्रदर्शनी एवं आयोजन इस शुल्क से छट के दायरे में आएंगे।

इस विषय पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी में मौल में

खाद्य सामग्री की अधिक दरों पर चिंता जहिर की। एमआईसी सदस्य अवतार सिंह बागल ने बताया कि खाद्य सामग्री के मूल्य पर नगरनिगम का नियंत्रण नहीं होता। पीने का पानी मुफ्त में मिलता है। बोतल बंद पानी का मूल्य निर्धारण नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आज की सामान्य सभा में संत रामदास वाडेकें अंतर्गत सामुदायिक भवन को पुलिस कमिश्नरेट उपायुक्त पश्चिम कार्यालय के संचालन के लिए दिए जाने संबंधी महापौर के निर्णय का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस के पार्षद श्रीमती रेनु साहू एवं अर्जुन देबर ने विरोध करते हुए कहा कि किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। सामुदायिक भवन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए होना चाहिए। वार्ड पार्षद भोलाराम ने कहा कि इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा होगी। यह प्रस्ताव भी पारित हो गया।

सामान्य सभा में खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों को मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंतर्गत क्रिस्टल आर्केड के सामने की भूमि में व्यवस्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए दुकानदारों से 129299 रुपए रुपए लागत ली जाएगी। कम से कम 55 दुकानदारों द्वारा राशि निगम कोर्स में जमा करने के बाद ही निर्माण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

आंगनबाड़ी संस्कार निर्माण की पाठशाला बने : लक्ष्मी राजवाड़े



रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें 'संस्कार निर्माण की पाठशाला' के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों के सर्वांगीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें दिए गए संस्कार जीवनभर उनकी सोच और व्यवहार को दिशा देते हैं।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र के ईसीसीई के राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर रही थीं। बैठक में प्रदेश के 52,518 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को संस्कारपरक शिक्षा से जोड़ने के लिए ठोस पहल करने पर विचार किया गया।

उन्होंने कहा कि बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर और आंगनबाड़ी होता है, इसलिए यहां दी जाने वाली शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। संस्कारपरक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही बड़ों का

सम्मान, सत्य बोलना, स्वच्छता, अनुशासन, प्रकृति प्रेम तथा 'धन्यवाद' और 'क्षमा' जैसे व्यवहारिक गुणों का विकास करना है। मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार की शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने दिन की शुरुआत प्रार्थना, योग और प्राणायाम से करने, पंचतंत्र एवं लोककथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने, त्योहारों और महापुरुषों की जयंती के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने, तथा दैनिक व्यवहार में 'नमस्ते', स्वच्छता और अनुशासन को शामिल करने पर बल दिया। साथ ही बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान और प्रकृति प्रेम विकसित करने के लिए पौधारोपण एवं स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे कार्यों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की बात कही। उन्होंने अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया हुए कहा कि महीने में 'संस्कार सभा' आयोजित कर माता-पिता को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए।

खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने टूर्नामेंट आवश्यक : साव



रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना कप का आयोजन अनेक वर्षों से हो रहा है। प्रदेश में लगातार खेल प्रतियोगिताएं होने से खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलता है और अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं। टूर्नामेंट में 20 राज्यों के 120 खिलाड़ियों का भाग लेना इसकी सफलता को बताता है। उप मुख्यमंत्री गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट के समापन समारोह में हुए शामिल

श्री साव ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ी टूर्नामेंट आवश्यक हैं। इसके बिना खेल और खिलाड़ी दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। गोंडवाना कप जैसी प्रतियोगिताएं लगातार होने चाहिए।

महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले में शताक्षी चौधरी और अनन्या जैन (उत्तर प्रदेश) की जोड़ी ने स्निग्धा पाटिबंडला और इरम जैदी की 3-6, 6-3, 10-7 से हराकर खिताब जीता। वहीं पुरुष डबल्स में निरव शेटी और

अनुप बंगाली (महाराष्ट्र) की जोड़ी ने प्रसाद इंगले और परितोष पवार को 6-2, 6-4 से हराया।

वहीं महिला एकल में राजस्थान की आयुषी तनवार ने उत्तरप्रदेश की शताक्षी चौधरी को 2-6, 6-2, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल में तेलंगाना के नैशिक रेड्डी गनागामा ने महाराष्ट्र के प्रसाद इंगले को 7-6 (7-4), 6-3 से हराकर विजेता बने। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। समापन समारोह में एआईटीए (डूड्ड) के महासचिव श्री अनिल धुपर, स्टेट टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी, श्री गुरुचरण सिंह होरा, उपाध्यक्ष श्री नरेश गुप्ता और श्री आशीष सराफ सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेलप्रेमी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने पुस्तक बिरहोर जननायक का किया विमोचन



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित पुस्तक बिरहोर जननायक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक के लेखक डॉ. लोकेश पटेल को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है और उनके कार्य विशेष रूप से जनसेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के

लिए प्रेरणास्रोत हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर जिले में 'बिरहोर के भाई' के रूप में विख्यात श्री जागेश्वर यादव ने बिरहोर आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व और समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और संवेदनशीलता से ही जन्म लेता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिरहोर जननायक पुस्तक उनके संघर्ष, समर्पण और सेवा की उस प्रेरक यात्रा को सामने लाती है, जो नई पीढ़ी को समाज के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनने की दिशा देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कृति पाठकों को न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि समाज के प्रति सकरात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक होगी।

केमिकल और औद्योगिक आपदा के लिए सचेत रहने की जरूरत

रायपुर। औद्योगिक एवं केमिकल डिजास्टर के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय औद्योगिक आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में औद्योगिक या केमिकल आपदा के अवसर की जाने वाली सावधानियां डिजास्टर के समय की व्यापक तैयारियां पहले से करने के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के



अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जानकारी दी गई कि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में केमिकल एवं औद्योगिक आपदा के संबंध में राज्य स्तरीय माँक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक या केमिकल आपदा के समय कैसे व्यापक प्रबंधन एवं सुरक्षा किया जाए। आपदा के समय आपातकालीन तैयारियां, अग्निशामक तैयारियां, आपदा के समय जन सामान्य में जागरूकता सहित विविध आपदा प्रबंधन के तौर-तरीकों और तैयारियों के संबंध में व्यापक मार्गदर्शन दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में गृह मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अन्य पुलिस फोर्स के अधिकारी सहित उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य, ग्रुह और राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी जिलों के जिला आपदा प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुये।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

महिलाओं को छोटी साड़ी शर्मनाक: दीपक बैज

रायपुर। पूरी की पूरी भाजपा सरकार कमीशनखोरी में लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना कमीशन के काम हो जाए। सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोटी साड़ी देकर सरकार ने भ्रष्टाचार की इंतहा को पार कर दिया। सरकार ने बहनों का चीरहरण घोटाला कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 6.3 मीटर की जगह 5 मीटर और 4.5 मीटर से भी कम लंबाई और चौड़ाई एवं घाटिया साड़ियां महिला एवं बाल विकास विभाग में वितरण किया गया है। साड़ियों के लंबाई और चौड़ाई में कम होने के कारण महिलाएं साड़ी का उपयोग नहीं कर पा रही। जो साड़ी हथकरघा के बुनकरों से 500 रु. में लेना था वही साड़ी गुजरात से 100 रु. में खरीद कर 500 रु. की बिलिंग करवा ली गयी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में एक महिला मंत्री के होते हुए महिलाओं के साथ उनके अधिकार पर डाका डाला जा रहा है और महिला मंत्री कमीशन-कमीशन खेल रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में यह पहली बार नहीं हुआ है।

आत्मानंद स्कूलों में फीस वसूलने का निर्णय गलत: शुक्ला

रायपुर। सरकार के द्वारा आत्मानंद स्कूलों में बच्चों से सालाना फीस वसूलने के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश के गरीब एवं ऐसे लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते उनके लिये अंग्रेजी माध्यम का आत्मानंद स्कूल शुरू किया था, दुर्भाग्यजनक है कि भाजपा सरकार आत्मानंद स्कूलों में भी बच्चों से फीस वसूलने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 750 आत्मानंद स्कूल शुरू किया था। जिसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाती और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को आत्मानंद स्कूलों में तबदील कर छत्तीसगढ़ को मुफ्त शिक्षा की ओर ले जाने की कार्य योजना बनाई गयी थी। भाजपा सरकार इस स्कूल में फीस वसूलने का निर्णय लेकर अन्याय कर रही है। मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य नागरिक का अधिकार है तथा नागरिकों को यह हदना सरकार का दायित्व भाजपा सरकार अपने दायित्व को पूरा करवाने मे असफल साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आत्मानंद स्कूल को बंद करने का षडयंत्र शुरू कर दिया गया है।

आयुष्मान पर रोक, तो मरीज का इलाज कैसे होगा: ठाकुर

रायपुर। आयुष्मान योजना से प्रदेश के कई निजी अस्पतालों को बाहर करने और कई को निलंबित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब मरीजों के सामने अपना इलाज कराने गभीर संकट उत्पन्न हो गया। सरकारी अस्पताल सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। अब आयुष्मान योजना के तहत जो निजी अस्पताल इलाज कर रहे थे, पहले तो उनका भुगतान नहीं किया गया। अब 33 से अधिक अस्पतालों को योजना से ही बाहर कर दिया गया। कई अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया। ये तो गरीब मरीजों के साथ सरकार की कूररता है। मरीज पहले ही बीमारी से लड़ रहे उन्हें अब इलाज कराने कर्ज लेना पड़ेगा, अपनी जमीन, जेवर गिरवी बेचना पड़ेगा। सरकार ने जिन निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किया है, निलंबित किया है, उसे गरीबों के हित में तत्काल आदेश वापस लेना चाहिए। क्योंकि इन निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से इलाज करने सरकार ने ही अधिकृत किया था। उस दौरान जब नियम कायदे सही थे तो अब गलत कैसे हो गया? निजी अस्पतालों से मांगी गई जानकारी के लिए उन्हें समय दिया जाये।

सरकार का चावल उत्सव ढकोसला : वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार के चावल उत्सव को ढकोसला बताते हुए कहा कि राशन दुकानों में चावल का स्टॉक पहुंचा नहीं है और सरकार चावल उत्सव मनाने का प्रोपोगंडा कर एक साथ तीन माह का चावल देने की बात कर रही, जबकि तीन दिनों से लोग राशन दुकानों में घंटो लाइन लगा कर वापस आ रहे हैं, उन्हें चावल नहीं मिल रहा। राशन दुकान के संचालक बताते हैं उनके पास स्टॉक ही नहीं है। जब दुकानों तक पर्याप्त मात्रा में राशन का स्टॉक नहीं पहुंचा तो सरकार ने लोगों को चावल उत्सव के नाम पर भीषण गर्मी में कतार में क्कों लगवाया ?प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पिछले पांच महीने से सरकार राशन दुकानों को नियमित राशन तो पहुंचा नहीं पायी है। पांच माह से राशन कार्डधारियों को चावल नहीं मिल रहा है और सरकार तीन महीने का चावल एकमुश्त देने का ढिंढोरा पीट कर चावल उत्सव मनाने जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक दुकानों में मात्र 30 प्रतिशत चावल ही उपलब्ध है, जब दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पाया है तो उपभोक्ता को कैसे चावल देगी सरकार? इस बात को कांग्रेस पहले से उठाते आ रही है।

कैट महिला विंग का महिला सशक्तिकरण

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा, महिला प्रदेश महामंत्री श्रीमती पिंकी अग्रवाल एवं महिला प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रेरणा भट्ट प्रदेश उपाध्यक्ष पल्लवी मनोदेव गौड़ा ने बताया कि आज कैट महिला विंग द्वारा महिला सशक्तिकरण समूह के अंतर्गत एक सफल एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष मधु अरोरा ने बताया कि अनमोल पारवानी ने वुमन इम्प्लायमेंट पर प्रजेन्टेशन दिया कि हम कैसे एक दुसरे की मदद कर सकते हैं कार्यक्रम का सफल संचालन दर्शना पंडया द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को रोचक एवं सुव्यवस्थित बनाए रखा। अरोरा ने आगे बताया कि यह कार्यक्रम कैट महिला विंग द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य जागरूकता एवं उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना था।

श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री, प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए की प्रार्थना

मानव जीवन दुर्लभ, सेवा से ही सार्थकता : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान श्री हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी द्वारा कही जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रीमद्भागवत का मूल संदेश यही है कि कर्म ही सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा कि हमें सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहकर मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीराम मंदिर में भगवान के दर्शन कर



प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमद्भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाललीला के अंतर्गत माखनचोरी के प्रसंग का भक्तिभाव के साथ श्रवण किया। उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर परिसर में 6 अप्रैल

जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और निरंतर प्रगति के पथ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया। उन्होंने कहा कि लगभग पांच हजार वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ का जंगल ही दंडकारण्य क्षेत्र है और शिवरीनारायण माता शबरी की पावन भूमि है। गुरु चासीदास जैसे महान संतों की जन्मभूमि होने के कारण छत्तीसगढ़ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध प्रदेश है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रभु श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 42 हजार भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं तथा 5 हजार से अधिक बुजुर्गजन देश के विभिन्न तीर्थस्थलों के दर्शन कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य का नानू लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत देश के अन्य राज्यों की तुलना में कठोर प्रावधान किए गए हैं।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है। जहां में सामने आया कि कई अस्पतालों ने नए पोर्टल एचईएम 2.0 पर न तो आवेदन किया और न ही

अनुसार समयबद्ध तरीके से पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करें, ताकि मरीजों को निर्बाध सेवाएं मिलती रहें।

आगे भी जारी रहेगी सख्ती

स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।